लखनऊ

शुक्रवार 27 फरवरी, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 188

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

"जीवन खूबसूरत तब बनता है जब जीत की उम्मीद, हार के डर से ज़्यादा मजबूत हो जाती है।"

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi

NIGHT 10° Low

मोदी इजराइल के होलोकॉस्ट मेमोरियल पहुंचे: हिटलर शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी, नेतन्याहू से मीटिंग थोड़ी देर में

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन है। वे गुरुवार सुबह यरूशलम के होलोकॉस्ट मेमोरियल 'याद वाशेम' पहुंचे। यहां उन्होंने हिटलर के नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मिले। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान इसाक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इजराइल के दिलों में भारतीयों के प्रति गहरा लगाव है।

मोदी थोड़ी देर में इजराइली PM नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक

करेंगे। इस बैठक में रक्षा सहयोग, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, साइबर सुरक्षा और एडवांस टेक्नोलॉजी के लेकर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है।

मोदी बुधवार को दो दिन के इजराइल दौरे पर पहुंचे थे। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने इजराइली संसद नेसेट को भी संबोधित किया। उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' दिया गया। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशेम में एक पौधा लगाया।

भारत पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा: इजराइली राष्ट्रपति

मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के बीच बातचीत शुरू हो गई है। इसाक ने मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। उन्होंने कुशल भारतीय छात्रों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह चाहते है कि भारतीय छात्र इजराइल आए और पढ़ाई करे।

हिटलर के शासन में मारे गए यहूदियों की याद में बना 'यद वाशेम' स्मारक

याद वाशेम होलोकॉस्ट के दौरान मारे गए लाखों यहूदियों की याद में बनाया गया है। यह स्मारक इजराइल की राजधानी यरुशलम में स्थित है और हर साल दुनिया भर से लोग यहां आकर इतिहास को समझते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी। इस नरसंहार को होलोकॉस्ट कहा जाता है। इजराइल की संसद नेसेट ने साल 1953 में फैसला किया कि होलोकॉस्ट में मारे गए लोगों की याद में एक खास स्मारक बनाया जाए। बाद में 2005 में यहां एक आधुनिक संग्रहालय खोला गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस त्रासदी को समझ सकें। याद वाशेम परिसर में होलोकॉस्ट संग्रहालय, हॉल ऑफ नेम्स, बच्चों का स्मारक और राइटियस अमंग द नेशंस गार्डन जैसी जगहें मौजूद हैं। यहां असली दस्तावेज, तस्वीरें और पीडितों की व्यक्तिगत कहानियां सुरक्षित रखी गई हैं। याद वाशेम नाम का अर्थ है याद और नाम, यानी जिन लोगों को मिटाने की कोशिश की गई, उनकी याद हमेशा जिंदा रहे।

इजराइल के दिलों में भारत के प्रति गहरा लगाव: मोदी

मोदी बोले- इजराइल के दिलों में भारत और भारतीयों के प्रति गहरा लगाव है। भारत और इजराइल का संबंध मजबूती के साथ काम आ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत-इजराइल संबंधों का उपयोग कई क्षेत्रों में वैश्विक भलाई को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। चाहे वह साइंस, इनोवेशन, एजुकेशन या एग्रीकल्चर हों। कुछ ऐसे क्षेत्र जिनमें हमारी विशेषज्ञता है, इनमें भारत, इजराइल की अच्छी चीजों को लागू करने की कोशिश कर रहा है और इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

संक्षेप

पुलिस थानों में खराब सीसीटीवी पर सख्त कोर्ट, केंद्र को बैठक में शामिल होने के निर्देश; 14 मार्च को अहम मीटिंग

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी को लेकर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को निर्देश दिया है कि वे एक केंद्रीयकृत डैशबोर्ड और सीसीटीवी मानकीकरण से जुड़ी बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लें। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे द्वारा दी गई दलीलों के बाद यह आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश एमिकस क्यूरी (न्यायालय का मित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे की दलील पर दिया। दवे ने बताया कि 21 फरवरी को हुई बैठक में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और कुछ राज्य शामिल नहीं हुए, जिससे रिपोर्ट दाखिल नहीं हो सकी। इस दलील पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि भारत सरकार के वकील ने पहले ही क्षमा मांग ली है कि संचार में कुछ गड़बड़ी के कारण वे बैठक में शामिल नहीं हो सके। हालांकि, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगली बैठक में वे पूरा सहयोग देंगे। पीठ ने कहा कि अतिरिक्त मित्र ने बैठक के लिए 14 मार्च, 2026 की तारीख सुझाई है। बैठक पहले दिए गए निर्देशानुसार 14 मार्च, 2026 को आयोजित की जाए। कोर्ट ने कहा कि अगली बैठक 14 मार्च 2026 को होगी और सभी पक्षों को सहयोग करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को तय की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पुलिस थानों में मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के लिए सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया था।

हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, शादी के बाद मैं भी, बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हिंदुओं से तीन बच्चे पैदा करने की अपील के बाद अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू आबादी को लेकर चिंता जताते हुए 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों राजस्थान के पुष्कर में तीन दिवसीय हनुमान कथा के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। हिंदू आबादी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक विषय है और भारत के संदर्भ में गंभीर चिंता का विषय है। उनके अनुसार, घटती हिंदू आबादी देश के भविष्य के लिए चुनौती बन सकती है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम चार बच्चे पैदा करने चाहिए। अपने अविवाहित होने को लेकर उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि लोग उनसे उनके योगदान के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन विवाह के बाद वह भी इस दिशा में योगदान देंगे। 'घर वापसी' के सवाल पर उन्होंने दावा किया कि भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने एक फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि लोग अपने मूल को समझें तो 'घर वापसी' संभव है। इसके अलावा, उन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाने वाले हिंदू श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में आस्था रखनी चाहिए। उन्होंने गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि अपने धर्म का पालन करना ही उचित मार्ग है।

डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में किया बदलाव, नहीं लगेगा 48 घंटे के भीतर कोई अतिरिक्त शुल्क

नई दिल्ली, एजेंसी। विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में संशोधन किया है। अब यात्री हवाई टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। डीजीसीए ने यात्रियों के अनुकूल संशोधित नियम जारी किए हैं। इसके तहत एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि यात्री टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में कोई गलती दिखाए और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो, तो इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डीजीसीए ने कहा, यदि टिकट ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी क्योंकि एजेंट

उनके नियुक्त प्रतिनिधि हैं। एयरलाइन यह सुनिश्चित करें कि रिफंड प्रक्रिया 14 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो। इसके अलावा, यात्री या उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा आपात स्थिति के कारण टिकट रद्द करने की शर्तों में भी बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन इसलिए किया गया है, क्योंकि पिछले समय में यात्रियों की शिकायतें बढ़ रही थीं कि उन्हें समय पर रिफंड नहीं मिल रहा।

संपत्तियों का ब्योरा न देने वाले राज्यकर्मियों के वेतन को लेकर हुआ फैसला, इस शर्त के साथ मिलेगी सैलरी

नई दिल्ली, एजेंसी। मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न करने वाले राज्य कर्मचारियों को सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक अंतिम अवसर दिया है। इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 31 जनवरी 2026 तक विवरण न देने वाले 47,816 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उनका वेतन रोका जाएगा। हालांकि 10 मार्च तक संपत्ति का विवरण देने वाले अधिकारियों का जनवरी का वेतन जारी कर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक में बताया गया है कि पूर्व में 24 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना था।

6 जनवरी 2026 को यह भी स्पष्ट किया गया था कि जो कर्मचारी निर्धारित तिथि तक विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी का वेतन फरवरी में नहीं दिया जाएगा। एनआईसी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 31 जनवरी तक 47,816 कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक बार फिर अवसर प्रदान किया है, लेकिन इसे कड़े प्रतिबंधों के साथ जोड़ा गया है। शासनादेश के अनुसार संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

देय होने पर भी इस वर्ष एसीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी ने विवरण अपलोड नहीं किया है और इसके बावजूद उसका जनवरी 2026 का वेतन आहरित किया गया है, तो संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी 10 मार्च 2026 तक अपना संपत्ति विवरण पोर्टल पर दर्ज कर देंगे, उन्हें जनवरी और फरवरी 2026 का वेतन तत्क्षण भुगतान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है।

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने किया तीन सदस्यीय पैनल का पुनर्गठन

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति का पुनर्गठन कर दिया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से 25 फरवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक, पुनर्गठित समिति 6 मार्च से प्रभावी होगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा बुधवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अरविंद कुमार पुनर्गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य सदस्य होंगे। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पुनर्गठित पैनल

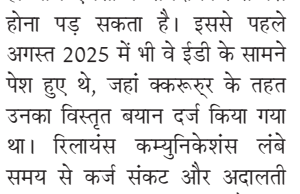

6 मार्च से प्रभावी होगा। यह कदम मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की निर्धारित सेवानिवृत्ति के बाद उठाया गया है, जो अगस्त 2025 में संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस भेजे जाने के बाद गठित मूल तीन सदस्यीय समिति का हिस्सा थे। उनके स्थान पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर को पैनल में शामिल किया गया है, जबकि अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अरविंद कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य सदस्य के रूप में बने रहेंगे।

'किसान की सुरक्षा-सम्मान से ही भारत सफल होगा', राहुल ने सरकार को यूएस ट्रेड डील पर घेरा

कन्नूर, एजेंसी। केरल दौरे पर पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्र सरकार को घेरा। कन्नूर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत तभी सफल हो सकता है जब हमारे किसानों का सम्मान और सुरक्षा हो। दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पेरावूर में किसान सम्मेलन में शामिल हुए। जहां उन्होंने कहा, 'मैं जब भी किसानों के बारे में सुनता हूं तो वे हमेशा दुख और तकलीफ सहते रहते हैं। सच तो यह है कि आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जब आप बोल रहे थे, उस समय मैं इस बिल्डिंग के बारे में सोच रहा था।

बिल्डिंग बनाने के लिए उसे सही नींव के बिना बनाना मुमकिन नहीं है... जैसे बिल्डिंग को नींव की जरूरत होती

है, वैसे ही देश को भी नींव की जरूरत होती है। नींव के बिना देश नहीं बन सकता। सीधी सी बात यह है कि हमारे किसान और खेती ही भारत की नींव हैं। आईटी और बाकी सब पर लंबे-लंबे लेक्चर दिए गए हैं, लेकिन इस देश की नींव, जो हमारे भारतीय किसान हैं, उनके बारे में बात नहीं की गई।'

केरल के संदर्भ में, हम अपना घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। मैं आप (किसानों) से अपने सुझाव देने का आग्रह करता हूँ। अगली सरकार, यूडीएफ सरकार को यह याद रखना चाहिए कि केरल की ताकत उसके किसानों और मजदूरों में निहित है। सरकार को किसानों तक सेवा प्रदाता के रूप में पहुँचना चाहिए, न कि उनकी समस्याओं के आने का इंतजार करना चाहिए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, कोल्ड-चेन और भंडारण सुविधाएँ, और मुश्किल समय में सुरक्षा जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों की बलि दी जा रही है ताकि प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा और भाजपा की आर्थिक नींव को बचा सकें।

अनिल अंबानी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई स्थित 3716 करोड़ का आलीशान घर किया कुर्क

मुंबई, एजेंसी। अनिल अंबानी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान घर 'अबोड' को कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई है।

अंबानी का यह बंगला मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल में स्थित है और इसकी गिनती भारत के महंगे आवासीय परिसरों में होती है। 66 मीटर ऊंची इस इमारत में 17 मंजिलें हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य लगभग 3716.83 करोड़ रुपये आंका गया है।

यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के तहत की गई है।

ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अस्थायी आदेश जारी कर इस मल्टी-स्टोरी इमारत को अटैच किया है। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी के जरिए बैंकों के साथ धोखाधड़ी की गई और धन का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। ताजा आदेश के बाद, इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 15,700 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 66 वर्षीय अनिल अंबानी को जल्द ही जांच एजेंसी के समक्ष फिर से पेश होना पड़ सकता है। इससे पहले अगस्त 2025 में भी वे ईडी के सामने पेश हुए थे, जहां क्कररूर्र के तहत उनका विस्तृत बयान दर्ज किया गया था। रिलायंस कम्युनिकेशंस लंबे समय से कर्ज संकट और अदालती कार्रवाइयों का सामना कर रही है। एक समय देश के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल रहे अनिल अंबानी के लिए अपने आवास की कुर्की व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से बड़ा झटका माना जा रहा है।

'बच्चे ये पढ़ेंगे कि न्यायपालिका करप्ट है', सीजेआई सूर्यकांत ने एनसीईआरटी विवाद पर कहा- हम पता लागाएंगे इसके पीछे कौन है?

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इस मामले पर सुनवाई करते एनसीईआरटी को जमकर फटकार लगाई। सूर्यकांत बहस के दौरान काफी गुस्से में दिखे। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा को कम करने के लिए एक कैलकुलेटिव मूव है। मैं न्यायपालिका का मुखिया होने के नाते जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता है तब तक इस मामले की सुनवाई जारी रहेगा। 'बच्चे ये पढ़ेंगे कि न्यायपालिका करप्ट है' 8वीं के किताब में ये बातें... वहीं NCERT ने कहा कि वो इस केस में बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। कोर्ट में सॉलसिटर जनरल ने बताया कि जो 32 किताबें बिकी थीं, उनको वापस ले लिया है।

इस पर सीजेआई ने कहा कि ये 8वीं क्लास के बच्चों की बात नहीं हैं। ये कैलकुलेटिव मूव यानी सोच समझा तरीका है। मैं इसका पता लगाउंगा। इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनसीईआरटी के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला केवल कुछ किताबों या उनमें छपी गलतियों का नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का एक सोचा-समझा प्रयास यानी 'कैलकुलेटिव मूव' प्रतीत होता है।

सुनवाई शुरू होते ही सीजेआई सूर्यकांत ने एनसीईआरटी के वकीलों और अधिकारियों को आड़े हाथों लिया।

क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद एनसीईआरटी की किताबों में कुछ ऐसी सामग्री और संदर्भों को लेकर शुरू हुआ था, जो कथित तौर पर न्यायपालिका के फैसलों को गलत तरीके से पेश कर रहे थे या अदालती आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। पिछली सुनवाइयों में भी कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा था। आज की सुनवाई ने यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अब शिक्षा और संवैधानिक मर्यादा के बीच किसी भी तरह के खिलवाड़ को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

उन्होंने कहा, 'यह जो कुछ भी किया गया है, वह कोई अनजानी भूल नहीं है। यह न्यायपालिका की गरिमा को कम करने के लिए एक बेहद कैलकुलेटिव मूव है।' सीजेआई ने आगे स्पष्ट किया कि वह इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा, 'मैं इस न्यायपालिका का मुखिया हूं और जब तक मैं व्यक्तिगत रूप से इस पूरी प्रक्रिया और सुधारों से संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। हम इसे तार्किक अंत तक लेकर जाएंगे।'

बिना शर्त माफी भी NCERT के काम नहीं आया

एनसीईआरटी ने अदालत के समक्ष 'बिना शर्त माफी' मांगने का प्रस्ताव रखा। संस्थान ने कहा कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को सूचित किया कि विवादित सामग्री वाली जो 32 किताबें बाजार में बिक चुकी थीं, उन्हें वापस ले लिया गया है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि आगे भी इस तरह की किसी भी विवादित किताब को वितरण प्रक्रिया से पूरी तरह हटा दिया गया है।

बचाव पक्ष की दलील

जब बचाव पक्ष ने इसे एक सामान्य प्रक्रियात्मक चूक बताने की कोशिश की, तो सीजेआई सूर्यकांत ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, 'यह केवल 8वीं क्लास के बच्चों की किताबों की बात नहीं है। आप इसे छोटा मामला मत समझिए। यह पूरा घटनाक्रम एक खास पैटर्न की ओर इशारा करता है, जिसका मकसद संवैधानिक संस्थाओं की छवि को धूमिल करना है। यह पूरी तरह से सोच-समझकर अपनाया गया एक तरीका है।'

कोर्ट रूम में हुई बहस की लाइन टू लाइन मुख्य बातें

सीजेआई सूर्यकांतः आप जो माफी मांग रहे हैं, क्या वह केवल सजा से बचने के लिए है या आपको अपनी गलती का एहसास है? यह न्यायपालिका की गरिमा पर प्रहार है।

सॉलिसिटर जनरलः लॉर्डशिप, हमने उन सभी 32 प्रतियों को ट्रैक करके वापस मंगा लिया है जो सर्कुलेशन में थीं। हम इसे लेकर बेहद गंभीर हैं।

कब होगा होलिका दहन और कब खेली जाएगी रंगों की होली? 3 या 4 मार्च, ज्योतिषाचार्य से जानें सही तिथि

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। इस वर्ष होली पर पर दुर्लभ और महत्वपूर्ण खगोलीय संयोग देखने को मिलेगा। 2 मार्च की शाम को 5:56 के उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 2 तारीख को भद्रा भी 5:56 के उपरांत प्रारंभ हो रही है और अर्ध रात्रि में 29:29 तक रहेगी। श्री निर्णय सागर पंचांग के अनुसार भद्रा के संबंध में शास्त्रों में लिखा गया है यदि भद्रा निशीथ काल यानी मध्य रात्रि के बाद तक रहे तो फिर भद्रा में ही प्रदोष के समय भद्रा का मुख छोड़कर होलिका का दहन करें। इस वर्ष भद्रा का मुख नहीं रहेगा इससे प्रदोष बेला सूर्यास्त से 2 घंटे 24 मिनट में ही होलिका का दहन करना शास्त्रोक्त है।

सूर्यास्त का समय 2 तारीख को सांयकाल 6:36 पर है इसके उपरांत होली दहन करने का समय 9:00 बजे

तक शुभ रहेगा। तीन तारीख को खग्रास/ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का विरल छाया में प्रवेश 2:14 पर मध्यान्ह के समय, स्पर्श दोपहर 3:20 से प्रारंभ होगा और मोक्ष 6:45 पर होगा। चंद्र ग्रहण के सूतक 9 घंटे पूर्व से प्रारंभ होते हैं, अतः सूर्योदय के समय चंद्र ग्रहण के सूतक प्रारंभ रहेंगे और शाम को पूर्णिमा 5:08 तक ही रहेगी। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में ही किया जाता है, अतः निर्णय सागर पंचांग के अनुसार 2 तारीख को ही होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत रहेगा।

4 मार्च को खेलें रंगों के साथ

3 मार्च को चंद्रग्रहण लग रहा है, यह ग्रहण 3 बजकर 20 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 46 मिनट तक लगेगा। भारत में ग्रहण चन्द्रोदय के साथ शाम 6 बजकर 14 मिनट से शुरू होगा और 6 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारम्भ हो जाता है, यानि कि सुबह 9 बजकर 20 मिनट से सूतक लगेगा। सूतक काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या उत्सव करना मना होता है। इसलिए रंगोत्सव करना शास्त्र सम्मत नहीं है, इसके चलते 3 मार्च को होली नहीं खेली जाएगी। चंद्रग्रहण और सूतक की वजह से 4 मार्च को रंगों का त्योहार मनाया जाएगा।

चंद्र ग्रहण में क्या करें

चंद्र ग्रहण के समय अपने इष्ट देव के मत्रों का जाप करें। ग्रहण काल का समय साधना के लिए विशेष फलदाई माना जाता है। अपने घर के मंदिर का भी पट बंद रखें। गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। चाकू से कुछ भी चीज काटना छीलना आदि नहीं करना चाहिए।

सफेद वस्तुओं का करें दान

चंद्र ग्रहण के उपरांत सभी लोगों को चंद्रमा के निमित्त सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत अपने घर के भगवान जी को भी स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कराएं। होली भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है जो खुशी, आनंद, प्रेम और एकता का प्रतीक है। होली का पर्व परस्पर विभिन्न गतिविधियों, नृत्य ,संगीत, खाने पीने और खुशी के साथ मनाना चाहिए।

रामपुर में दो प्लाईवुड फैक्ट्रियों का सर्वे शुरू, दिल्ली से सीआरपीएफ जवानों के साथ पहुंची एजेंसी की टीम

आर्यावर्त संवाददाता

रामपुर। रामपुर की दो बड़ी प्लाईवुड फैक्ट्रियों पर दिल्ली से आई एक एजेंसी की टीम ने जांच शुरू कर दी है। सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में पहुंची टीम ने फैक्ट्रियों के गेट बंद करवा दिए। अचानक हुई इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों में हलचल है। जांच एजेंसी के सर्वे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं किया है।

यह दोनों प्लाईवुड फैक्ट्रियां रामपुर के जाने-माने कारोबारियों की बताई जा रही हैं। इसमें एक कारोबारी मुरादाबाद से सपा के पूर्व सांसद के समधी हैं। जांच एजेंसी के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात है। फैक्ट्रियों के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उनके गेटों को भी बंद करवा दिया गया है। स्थायीन व्यापारियों के बीच इस सर्वे को लेकर हलचल मची हुई है। फैक्ट्रियों के मालिक और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

शादी समारोह से लौट रही पांच महिलाओं को पिकअप ने रौंदा ; तीन की मौत और दो मेडिकल कॉलेज रेफर

आर्यावर्त संवाददाता

महोबा। महोबा जिले में कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक पैलेस में बुधवार की रात आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में खाना बनाकर लौट रहीं पांच महिलाओं को पीछे से आ रही पिकअप ने कुचल दिया। हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है।

शहर के मोहल्ला कल्याण सागर निवासी स्व. फूलचंद्र की पत्नी भगवती (50), डाकबंगला निवासी स्व. बालकिशन की पत्नी गीता (35), भटीपुरा निवासी शंभू की पत्नी तुलसिया (65), अपनी बहू राजकुमारी उर्फ कपूरी (40) व भटीपुरा निवासी कालीचरण की पत्नी श्यामारानी (40) हाईवे स्थित मीना पैलेस में पूड़ी बनाने के लिए मजदूरी पर गईं थीं।

पिकअप ने पांचों महिलाओं को कुचल दिया

रात करीब ढाई बजे काम खत्म करके सभी महिलाएं पैदल घर लौट रही थीं। जैसे ही वह मां बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर के पास पहुंची, तभी छतरपुर की ओर से तेज रफ्तार पिकअप ने पांचों महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में भगवती और श्यामारानी की मौके पर मौत हो गई, जबकि गीता की जिला अस्पताल में उपचार दौरान दम तोड़ दिया।

पिकअप चालक के खिलाफ कोतवाली में दी तहरीर

वहीं, हादसे में घायल तुलसिया व उसकी बहू राजकुमारी को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है। श्यामारानी के बेटे संतोष ने पिकअप चालक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीओ अरुण कुमार सिंह और कोतवाली पुलिस ने मृतक के परिजनों से जानकारी ली। मामले की जांच की जा रही है।

कोर्ट ने आरोपी को लगी चोट नहीं दर्शाने पर डॉक्टर को किया तलब

सुलतानपुर। जानलेवा हमले एवं एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में आरोपी शिवम सिंह व छोटू गुप्ता उर्फ कृष्णा को गिरफ्तार कर बुधवार को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट जज राकेश पांडेय की अदालत में पेश किया गया। मामले में रिमांड पर सुनवाई के दौरान अदालत में पेश आरोपी की शरीर पर चोट का निशान दिखने के बावजूद प्रस्तुत की गई मेडिकल रिपोर्ट में चोट का जिक्र नहीं करने की वजह से अदालत ने मामले में चिकित्सक की कार्यशैली पर संज्ञान लिया है। अदालत ने मामले में आरोपियो का मात्र दो दिन का रिमांड स्वीकार किया है। स्पेशल जज ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए चिकित्सा अधिकारी डॉ एसपी शुक्ला को व्यक्तिगत रूप से 27 फरवरी के लिए तलब किया है। मामले की जांच सीओ कादीपुर को मिली है। दोनों आरोपियो पर इनाम घोषित रहने की भी जानकारी मिली है।

डीसी एनआरएलएम ने किया ब्लॉक का निरीक्षण

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

मोतिगरपुर/सुलतानपुर। डीसी एनआरएलएम के.डी. गोस्वामी ने गुरुवार को मोतिगरपुर ब्लॉक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीसी रुम, पंचायत कार्यालय, मनरेगा सेल,एनआरएलम डेस्क का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक सुधार के साथ मातहतो को स्टोर रूम मे निष्प्रयोज सामान की नीलामी व ग्रांट रजिस्टर में पड़े पुराने मदों के अवशेष पैसों का खर्चा या मदो में वापस करने का निर्देश दिया।

गुरुवार को ब्लॉक मे डीसी एनआरएलम के निरीक्षण से कर्मचारियों में हलचल रही। उन्होंने बीसी रूम, पंचायत कार्यालय, मनरेगा सेल और एनआरएलएम डेस्क का निरीक्षण किया। कार्यालय मे टूटे फर्नीचर को दुरुस्त व खुले मे रखी बैटरी पर कवर लगाने का कर्मचारियों को निर्देश के साथ ही कार्यालय परिसर, शौचालय और अन्य कक्षों की साफ-सफाई की स्थिति परखी तथा स्वच्छता व्यवस्था नियमित बनाए रखने पर जोर दिया। वरिष्ठ सहायक पटल पर जीपीएफ व सर्विस पासबुक अद्यतन नहीं पाया गया। एक सप्ताह मे व स्टोर रूम में निष्प्रयोग पाए गए सामानों की नीलामी के साथ ग्रांट रजिस्टर में पुराने मदों के पैसे अवशेष रहने पर खर्च या मदो में वापस करने का निर्देश दिया। डीसी ने कार्यालय में विकास संबंधी फाइलों की गहन जांच की। स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं बैंक प्रगति, सीआईएफ वितरण अभिलेख, मनरेगा मास्टर रोल, पंचायत विकास कार्य योजना जीपीडीपी के दस्तावेज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति सूची, ग्राम संगठन एवं क्लस्टर स्तरीय संघ की प्रगति रिपोर्ट के साथ वित्तीय लेखा-जोखा एवं ऑडिट रजिस्टर का अवलोकन किया। अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी निशा तिवारी, एडीओ समाज कल्याण ओपी सिंह, राजकिशोर सिंह, प्रभारी एडीओ पंचायत नितेश सिंह, संजय मिश्र, खंड प्रेरक आशीष पांडेय, सचिन कुमार, शुभम कुमार तथा बीएमएम धर्मेंद्र सिंह आदि ब्लॉक कर्मी मौजूद रहे।

मंडल आयुक्त व डीएम पहुंचे लम्भुआ तहसील, निरीक्षण से मचा हड़कंप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। राजेश कुमार (मंडल आयुक्त, अयोध्या मंडल) और कुमार हर्ष (जिलाधिकारी, सुलतानपुर) ने आज लम्भुआ तहसील पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की सूचना मिलते ही तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी फाइलों को दुरुस्त करने में जुट गए।

निरीक्षण के दौरान राजस्व अभिलेखों, विकास कार्यों की प्रगति, जन शिकायतों के निस्तारण और कार्यालयी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से जानकारी ली और कई महत्वपूर्ण अभिलेखों की जांच भी की। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज रही कि क्या इस निरीक्षण में वास्तविक कमियां सामने आएंगी या फिर सब कुछ गुलाबी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। आमजन को उम्मीद है कि यह निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता न बनकर जमीनी स्तर पर सुधार लाने का माध्यम बनेगा। मंडल आयुक्त और डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस निरीक्षण के बाद व्यवस्थाओं में कितना सुधार आता है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है।

संभल के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च, त्योहारों को लेकर एसपी ने किया निरीक्षण, 500 लोग पाबंद

आर्यावर्त संवाददाता

संभल। रंग एकादशी, होली और रमजान के त्योहारों के मद्देनजर संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आरआरएफ, पुलिस और पीएसी के जवानों ने शहर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया।

सराय पुलिस चौकी से गश्त शुरू

बुधवार की शाम को पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने चौधरी सराय पुलिस चौकी से पैदल मार्च की शुरुआत की। यह मार्च शहर के विभिन्न संवेदनशील और मुख्य मार्गों से गुजरा। इसमें मनोकामना रोड, जामा मस्जिद, डाकखाना, मुख्य बाजार, कोतवाली, सराफा बाजार, नखासा चौराहा, खग्गू सराय और बल्ले की पुलिया शामिल थे। भोलेश्वर पुलिस चौकी क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान एसपी ने रंग एकादशी जुलूस के संभावित रूट का निरीक्षण किया और वहां मौजूद सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया।

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के कानून व्यवस्था को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पाबंद किए गए असामाजिक तत्व

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिलेभर में एहतियाती तौर पर 500 से अधिक ऐसे लोगों को पाबंद किया गया है। उनसे अशांति फैलाने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि जिले में लगातार गश्त की जा रही है।

यह अधिकारी रहे मौजूद

अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, कोतवाल गजेंद्र सिंह, कोतवाल नखासा संदीप बालियान सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।

डिप्टी सीएम की फोटो दिखाकर जलाशय पर बना विद्यालय, एसडीएम ने खतौनी में किया संशोधन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले के अलीगंज बाजार स्थित मनियारी गांव में सार्वजनिक जलाशय की भूमि पर विद्यालय और दर्जन भर से अधिक आवासीय भवन बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार की कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी ने संबंधित भूमि को पुनः जलाशय की श्रेणी में दर्ज कर दिया है।बताया जा रहा है कि गाटा संख्या 622, क्षेत्रफल लगभग 50 बिस्वा भूमि पर निर्माण पब्लिक स्कूल समेत कई मकान निर्मित हैं। आरोप है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक की फोटो दिखाकर अफसरों पर दबाव बनाया गया और निर्माण कार्य कराया गया। मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर से रिपोर्ट तलब की थी। तहसीलदार ने उच्च न्यायालय के हिंच लाल बनाम सरकार रिट का हवाला देते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत की थी,जिसमें भूमि की नवईयत त्रुटिवश परिवर्तित होने की बात कही गई थी। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए राजस्व वाद दर्ज कर एसडीएम सदर को अभिलेख संशोधन का निर्देश दिया था। आदेश के अनुपालन में एसडीएम सदर ने खतौनी में संशोधन कर भूमि को जलाशय के रूप में दर्ज कर दिया। इससे निर्माण पब्लिक स्कूल के प्रोपराइटर राजेश दूबे सहित अन्य भवन स्वामियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार विद्यालय और आवासीय भवनों को बचाने के लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत अवैध अतिक्रमण पर कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।

हाईकोर्ट में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज, यौन उत्पीड़न का केस है दर्ज

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 27 फरवरी को होगी। मामले की सुनवाई जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में होगी। शंकराचार्य और उनके शिष्य पर एक तथाकथित धर्मगुरु ने कथित तौर पर नाबालिगों के यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

दोनों नाबालिगों का न्यायालय में बयान दर्ज

दूसरी तरफ पुलिस ने दूसरे नाबालिग बालक का मेडिकल करवा लिया है। एसीपी झूंसी विमल कुमार मिश्र टीम संग गंगापार स्थित एक अस्पताल में नाबालिग को लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की पैनल टीम ने मेडिकल प्रक्रिया पूरी की। पुलिस को अब रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं दोनों बालकों को न्यायालय के समक्ष पेश कर बयान दर्ज करा दिया गया है। पुलिस अफसरों ने बताया कि एक टीम जल्द स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में जाकर पूछताछ करेगी।

मेडिकल रिपोर्टमें यौन उत्पीड़न की पुष्टि

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि मेडिकल जांच में होने का दावा किया जा रहा है। तेज प्रताप सप्रू अस्पताल बेली में दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। दो डॉक्टरों के पैनल ने जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसी दिन शंकराचार्य की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी है।

यौन शोषण में बड़े नेता व वीआईपी के शामिल होने का आरोप

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व उनके शिष्य पर पॉक्सो एक्ट की एफआईआर दर्ज कराने वाले एक जाने-माने धर्मगुरु के शिष्य ने कई अन्य सफेद पोश लोगों पर भी इस अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया है। कहा कि करीब 20 बच्चों का यौन शोषण किया गया है। लैपटॉप में नाबालिगों से यौन शोषण के वीडियो-फोटो के होने का दावा भी किया। आरोप है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में विद्यामठ सहित अन्य स्थानों पर भी यौन शोषण करते हैं। प्रतापगढ़ में पढ़ाई के दौरान भी बच्चों का शोषण किया गया। किसी भी आश्रम में जाने से पहले साजिश के तहत बच्चों को वीआईपी के सामने पेश किया जाता था। इन पीड़ितों में करीब 20 युवक-युवतियां भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने आलीशान भवन व स्विमिंग पूल के सबूत को मिटाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने एक बड़े नेता पर माघ मेला में अविमुक्तेश्वरानंद को धरने के लिए उकसाने का आरोप लगाकर कॉल डिटेल होने का दावा किया है। उन्होंने एफआईआर में नामजद लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है।

आधी रात को घर में लगी आग, लाखों का नुकसान

सुल्तानपुर। सदर तहसील क्षेत्र के धनपतगंज ब्लॉक स्थित केवटली ग्राम पंचायत के पूरे दत्ता राय निवासी राज नारायण कोरी पुत्र राम किशोर कोरी के घर में आधी रात को आग लग गई। जिससे उनकी पूरी गृहस्थी जल गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। तीन बकरियां झुलसकर मर गई।इसके अलावा एक पडिया भी झूलस ने से गंभीर है। तीन लोग भी आग से जल गए हैं। डायल 112 मौके पर पहुंची। इसके पहले ग्रामीणों ने एकजुट होकर के आग पर काबू पाया सूचना पर गुरुवार को हल्का लेखपाल कमलेश मौके पर पहुंचे। और नुकसान का आकलन कर और उपजिलाधिकारी बल्दीराय प्रवीण कुमार को रिपोर्ट देने की बात कही है। बसपा नेता हंसराज भारती ने बताया कि पीड़ति राज नारायण कोरी की माली हालत ठीक नहीं है। उन्होंने प्रशासन से सहायता प्रदान करने की मांग की है।

जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पर ऐतिहासिक समझौता

मुख्यमंत्री योगी ने निवेश रोड शो में रखा उत्तर प्रदेश का विकास विजन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। जापान दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर नई उपलब्धि हासिल की है। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्रों को जापान में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को प्रदेश के उद्योग, सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।यामानाशी में आयोजित निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश

की नई विकास नीति और निवेश संभावनाओं को वैश्विक उद्योग जगत के समक्ष विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने शासन की कार्यप्रणाली को प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था से आगे बढ़ाकर सक्रिय और दूरदर्शी मॉडल में परिवर्तित किया है। यही बदलाव आज उत्तर प्रदेश की तीव्र आर्थिक प्रगति का आधार बना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि टोक्यो में सरकार-से-सरकार और सरकार-से-व्यवसाय स्तर की कई महत्वपूर्ण बैठकों में प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, जहां भारतीय दूतावास के सहयोग से जापानी उद्योग समूहों के साथ व्यापक संवाद हुआ। उन्होंने यामानाशी प्रशासन द्वारा निवेश संवाद को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए आभार भी व्यक्त किया।मुख्यमंत्री ने भविष्य की तकनीकों पर विशेष बल देते हुए कहा कि रोबोटिक्स आने वाले समय की प्रमुख तकनीक है और प्रदेश सरकार ने अपने बजट में इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच सहयोग भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाई देगा तथा ऊर्जा और तकनीक को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 25 करोड़ की आबादी वाला यह राज्य देश की सबसे उर्वर भूमि, समृद्ध जल संसाधनों और विशाल मानव शक्ति से संपन्न है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा उत्तर प्रदेश आज देश की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनकर उभरा है।मुख्यमंत्री ने शासन व्यवस्था में आए परिवर्तन को रेखांकित करते हुए कहा कि पहले समस्याओं के समाधान के लिए केवल प्रतिक्रिया दी जाती थी, जबकि अब सरकार संभावनाओं की पहचान कर पहले से तैयारी करती है। निवेश को आकर्षित करने, उद्योगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने, नई तकनीकों को अपनाने और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में निरंतर पहल की जा रही है। इसी उद्देश्य से उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान की यात्रा पर आया है ताकि अवसरों को ठोस परियोजनाओं में बदला जा सके।यामानाशी प्रांत के साथ सहयोग को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रांत के राज्यपाल कोटारो नागासाकी और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जापान सरकार और यामानाशी प्रशासन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को अपने प्रमुख क्षेत्रों को समझने और उद्योग जगत से सीधे संवाद का अवसर प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने स्मरण कराया कि दिसंबर 2024 में यामानाशी के राज्यपाल उत्तर प्रदेश आए थे और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच लगातार संवाद, प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान और अध्ययन रिपोर्टों के आधार पर यह सहयोग अब ठोस समझौते में परिवर्तित हुआ है।

हर जिले में 100 मॉडल तालाब विकसित करने की तैयारी, ग्रे वाटर और प्लास्टिक से होंगे मुक्त

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के हर जिले में 100-100 तालाबों को 'मॉडल तालाब' के रूप में विकसित किया जाएगा। इन तालाबों को ग्रे वाटर और प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा, जिससे जल गुणवत्ता सुधरेगी और मच्छरजनित बीमारियों में कमी आएगी।

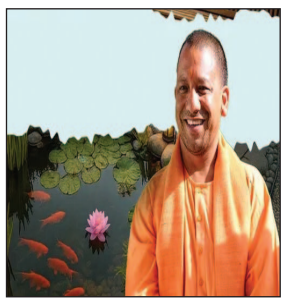

ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब केवल जल संग्रहण का साधन नहीं, बल्कि भू-जल रिचार्ज, सिंचाई, जैव विविधता संरक्षण और सामाजिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। लेकिन बीते वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट और घरेलू ग्रे वाटर (स्नान, रसोई व कपड़े धोने से निकला पानी) सीधे तालाबों में जाने से जल प्रदूषण बढ़ा है, जिसका सीधा असर ग्रामीण स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ा है। इसी चुनौती को देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पंचायती राज विभाग ने मॉडल तालाब विकसित करने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है।

पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह के अनुसार, चयनित तालाब के चारों ओर नो-प्लास्टिक जोन घोषित किया जाएगा और ग्राम पंचायत से प्लास्टिक न फेंकने का प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। तालाब में गिरने वाली नालियों पर प्लास्टिक ट्रैप जाली और फिल्टर चैंबर लगाए जाएंगे। वहीं, ग्रे वाटर के उपचार के लिए नालियों के अंतिम सिरे पर बायो-फिल्टर सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिसमें कंकड़, रेत और केली-केना जैसे पौधों का उपयोग होगा। इससे पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध होकर तालाब में पहुंचेगा।

आईटीबी बर्लिन–2026 में उत्तर प्रदेश की सशक्त उपस्थिति, वैश्विक मंच पर चमकेगा प्रदेश का पर्यटन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। विश्व पर्यटन उद्योग के प्रतिष्ठित मंच आईटीबी बर्लिन 2026 में उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक पर्यटन संभावनाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। 3 से 5 मार्च तक आयोजित होने वाले इस वैश्विक आयोजन में पर्यटन विशेषज्ञों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के समक्ष प्रदेश अपने विविध पर्यटन स्थलों, पर्यटन परिपथों, वेलनेस तथा साहसिक पर्यटन की व्यापक झलक प्रस्तुत करेगा।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आयोजन जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित बर्लिन एक्सपो सेंटर सिटी में किया जाएगा। वर्ष 1966 से यह आयोजन वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में स्थापित है और इस वर्ष अपने 60 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ विश्व समुदाय से संवाद करेगा।इस वर्ष आयोजन की थीम "डिस्कवर द स्टोरीज बिहाइंड 60 इयर्स ऑफ लेगेसी" रखी गई है, जो छह दशकों की उपलब्धियों, नवाचारों, साझेदारियों और पर्यटन उद्योग के विकास की प्रेरक गाथाओं को रेखांकित करती है।

यह थीम अतीत की विरासत का सम्मान करते हुए भविष्य की दिशा तय करने का संदेश देती है।आयोजन में पर्यटन क्षेत्र की बदलती प्राथमिकताओं और उभरते रुझानों को भी प्रमुखता दी जाएगी। प्रदर्शनी को केवल भौगोलिक आधार तक सीमित न रखकर साहसिक पर्यटन, व्यावसायिक यात्रा, समावेशी यात्रा, विलासिता पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और यात्रा प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न बाजार वर्गों में विभाजित किया गया है, ताकि विविध रुचि रखने वाले यात्रियों और उद्योग से जुड़े हितधारकों को समुचित अवसर मिल सके।मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर भव्य पवेलियन के माध्यम से अपनी पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करेगा।

पवेलियन में आकर्षक संकेतक और प्रदर्शन सामग्री अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में प्रदर्शित की जाएगी। विशेष अतिथि कक्ष, रचनात्मक साज-सज्जा, हस्तशिल्प, कलाकृतियां तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना के उत्पादों को भी प्रमुखता से रखा जाएगा। साथ ही प्रदेश की पर्यटन वेबसाइट और मोबाइल अनुप्रयोग को भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे वैश्विक मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को नई पहचान और मजबूती मिल सके।

ग्लोबल एग्रोटेक 2026 में बी .एल . एग्रो ने दिखाई कृषि नवाचार की शक्ति, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया शुभारंभ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बी.एल. एग्रो ने लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में आरंभ हुए 'ग्लोबल एग्रोटेक 2026' प्रदर्शनी एवं सम्मेलन के प्रथम दिवस पर कृषि क्षेत्र में अपनी विविध क्षमताओं और नवाचारों का व्यापक प्रदर्शन किया। तीन दिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। उद्घाटन अवसर पर वरिष्ठ नीति-निर्माताओं, विभिन्न देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिकों, शोध संस्थानों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और प्रगतिशील किसानों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उद्यान, कृषि विपणन एवं निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह तथा प्रमुख सचिव, कृषि रविंदर भी मौजूद रहे।शुभारंभ के बाद

उपमुख्यमंत्री ने बी.एल. एग्रो समूह के पवेलियन का अवलोकन किया और कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, एकीकृत मूल्य श्रृंखला, दुग्ध विकास, वैज्ञानिक आनुवंशिकी एवं जीनोमिक अनुसंधान, कृषि तकनीक मंच तथा जलवायु आधारित जोखिम विश्लेषण तंत्र जैसे क्षेत्रों में समूह के योगदान की जानकारी प्राप्त की। समूह की सहायक इकाइयों— लीड्स कनेक्ट, लीड्स जेनेटिक्स और लीड्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स—ने भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिससे कृषि की समग्र मूल्य श्रृंखला में समूह की सुदृढ़ होती भूमिका स्पष्ट हुई।ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से कृषि उन्नति और खाद्य प्रसंस्करण उत्कृष्टता का प्रमुख केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीक आधारित कृषि सुधार, मूल्य संवर्धन और किसान सशक्तिकरण पर विशेष बल दे रही है। ऐसे आयोजन तकनीक, उद्यमिता और ग्रामीण विकास के बीच मजबूत सेतु का कार्य करते हैं और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं।दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि यह अवसर भारतीय कृषि के अगले विकास चरण की दिशा तय करने का है। उत्तर प्रदेश देश की कृषि व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाता है और सतत कृषि विकास के लिए सार्वजनिक-निजी सहभागिता मॉडल अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर दीर्घकालिक कृषि विकास की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करते हैं।कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए बी.एल. एग्रो एवं आईसीएफए यूपीएसएसी के अध्यक्ष घनश्याम खंडेलवाल ने कहा कि यह आयोजन देश की कृषि यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कृषि क्षेत्र देश की सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय योगदान देता है और बड़ी जनसंख्या की आजीविका इससे जुड़ी है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने, दुग्ध क्षेत्र के आधुनिकीकरण, कृषि वित्त की पहुंच बढ़ाने तथा तकनीक-सक्षम कृषि तंत्र को प्रोत्साहित करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।उद्घाटन दिवस पर होटल रेडिसन लखनऊ सिटी सेंटर में 'उत्तर प्रदेश कृषि विकास बैठक' का आयोजन भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता घनश्याम खंडेलवाल ने की, जिसमें अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य पालन मुकेश कुमार मेश्राम तथा प्रमुख सचिव, कृषि रविंदर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

○ संक्षेप ○

यूपी प्रेस क्लब में युवा पत्रकारों विधि सिंह और मोहम्मद इरफान को श्रद्धांजलि, 27 फरवरी को शोकसभा

लखनऊ। मुख्यधारा के दो प्रमुख युवा पत्रकार स्वर्गीय विधि सिंह और स्वर्गीय मोहम्मद इरफान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यूपी प्रेस क्लब, लखनऊ में 27 फरवरी 2026, शुक्रवार को अपराह्न ढाई बजे शोकसभा का आयोजन किया गया है।दोनों पत्रकारों का इसी सप्ताह आकस्मिक निधन हो गया। स्वर्गीय विधि सिंह का निधन हृदयाघात से तथा स्वर्गीय मोहम्मद इरफान का निधन मस्तिष्काघात के कारण हुआ। उनके असामयिक निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है।स्वर्गीय विधि सिंह अपराध संवाददाता के रूप में अपनी तेज-तर्रार और निर्भीक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे, जबकि स्वर्गीय मोहम्मद इरफान अल्पसंख्यक मामलों की रिपोर्टिंग में एक सशक्त और संवेदनशील आवाज माने जाते थे। दोनों ने अपनी प्रतिबद्धता, मेहनत और निष्पक्ष लेखनी से पत्रकारिता जगत में विशेष पहचान बनाई थी।शोकसभा में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित होकर दोनों दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तथा उनके योगदान को स्मरण करेंगे।

दुबग्गा में युवक पर जानलेवा हमला और लूट का खुलासा, 'गद्दी गैंग' के पांच आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। कोतवाली दुबग्गा क्षेत्र में युवक पर जानलेवा हमला कर नगदी और महंगे मोबाइल फोन लूटने की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए कथित 'गद्दी गैंग' के पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की।पुलिस के अनुसार 25 फरवरी 2026 को फैय्याज पुत्र सखावत अली निवासी ग्राम छन्दोइया, कोतवाली दुबग्गा, लखनऊ ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि विपक्षीगणों ने एक राय होकर उनके पुत्र नोमान पर जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में नोमान गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके पास से 20 हजार रुपये नगद, एक आईफोन और एक सैमसंग मोबाइल फोन भी गायब कर दिए गए। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 066/2026 धारा109(1)/ 190/ 191(2)/ 191(3)/ 324(4)/ 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और नामजद व प्रकाश में आए पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।

मोहनलालगंज में 28 फरवरी को वृहद पशु आरोग्य मेला, पशुपालकों को मिलेंगी नि:शुल्क सुविधाएं

लखनऊ। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता योजनाओं के अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 28 फरवरी 2026 को प्रातः 8:00 बजे से जनपद लखनऊ के मजरा गनियार, ग्राम पंचायत भौंदरी, विकासखंड मोहनलालगंज में पं. दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेला/शिविर (मंडल स्तर) का आयोजन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि मेले में पशुपालकों को विभिन्न प्रकार की नि:शुल्क और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविर में रोगी पशुओं का विशिष्ट उपचार एवं औषधि वितरण, अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा जांच, कृत्रिम गर्भाधान एवं बांझपन समस्या का निवारण, लघु शल्य चिकित्सा तथा नि:शुल्क टीकाकरण की व्यवस्था रहेगी। साथ ही पशुधन बीमा की सुविधा एवं उन्नत पशुपालन तकनीकों की जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा प्रदान की जाएगी।पंजीकृत पशुपालकों को पशुओं के लिए नि:शुल्क कृमिनाशक दवा, खनिज लवण मिश्रण और सघन पशु आहार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। कृषि, उद्यान और मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएगी।मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने जनपद के सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने पशुओं के साथ मेले में पहुंचकर विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं।

सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन और हुड़दंग के खिलाफ लखनऊ पुलिस का विशेष अभियान, 326 व्यक्तियों पर कार्रवाई

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक विशेष अभियान चलाया। यह अभियान 25 फरवरी 2026 की रात 9 बजे से 11 बजे तक जनपद के सभी जोनों में एक साथ संचालित किया गया। अभियान के दौरान कुल 329 स्थानों पर सघन चेकिंग की गई और 2211 व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें से 326 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पाए जाने पर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान किया गया।यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशों तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार के पर्यवेक्षण में की गई। जनपद के सभी जोनों के पुलिस उपायुक्तों के नेतृत्व में सहायक

पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों की टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों, पार्कों, बाजारों, बस अड्डों, चौराहों और अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर अभियान चलाया।पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन कर हुड़दंग करते हैं, जिससे राहगीरों, महिलाओं और आम नागरिकों को असुविधा होती है तथा यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया।अभियान के दौरान मध्य जोन में 79 स्थानों पर 453 व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें 28 के खिलाफ कार्रवाई हुई। पूर्वी जोन में 58 स्थानों पर 378 व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 33 लोगों का चालान किया गया। दक्षिणी जोन में 46 स्थानों पर 259 व्यक्तियों की जांच में 25 के खिलाफ कार्रवाई की गई। पश्चिमी जोन में सर्वाधिक 116 स्थानों पर 846 व्यक्तियों की जांच की गई, जहां 204 लोगों पर कार्रवाई हुई। उत्तरी जोन में 30 स्थानों पर 275 व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 36 लोगों का चालान किया गया।पुलिस ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की कड़ी चेतावनी भी दी गई है। पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर ने कहा कि आमजन की शिकायतों के दृष्टिगत यह विशेष अभियान चलाया गया है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध तत्काल और सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।लखनऊ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हुड़दंगई से दूर रहें। पुलिस का उद्देश्य शहर में शांति, सुरक्षा और अनुशासित वातावरण बनाए रखना है, ताकि सभी नागरिक निर्भय होकर अपने दैनिक कार्य कर सकें।

जनसुनवाई में मंत्री ए .के . शर्मा ने अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज अपने आवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित, पारदर्शी तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए।जनसुनवाई के दौरान विद्युत कनेक्शन से जुड़े प्रकरण, विद्युत बिलों में त्रुटि सुधार, सीवर लाइन की समस्याएं, नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति, क्षतिपूर्ति भुगतान सहित विभिन्न स्थानीय जनसमस्याएं प्रमुख रूप से उठाई गईं। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए और उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिक प्रक्रिया न बनकर परिणाम देने वाली व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोगों को वास्तविक राहत मिल सके।मंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि विद्युत और नगर विकास से संबंधित मामलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर अनावश्यक विलंब न किया जाए। अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ नागरिकों की समस्याओं का समाधान करें तथा आवश्यकता पड़ने पर स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें।उन्होंने दोहराया कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध हों और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता बनी रहे।

मानव सम्पदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति विवरण न देने वाले 47,816 कर्मियों पर सख्ती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने मानव सम्पदा पोर्टल पर नियमानुसार चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न करने वाले राज्य कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित अवधि तक संपत्ति विवरण अपलोड न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा उन्हें पदोन्नति, एसीपी और सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जाए।

कार्मिक अनुभाग-5 से जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में जारी शासनादेशों के माध्यम से सभी राज्य कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अंतर्गत अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से 31 जनवरी 2026 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे।

भारत मंडपम में म्युनिसिपालिका–2026 सम्मेलन में शामिल हुईं महापौर सुषमा खर्कवाल, लखनऊ के विकास मॉडल पर रखे विचार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित तीन दिवसीय 'म्युनिसिपालिका-2026 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सुरक्षित, स्मार्ट और सतत शहर समाधान सम्मेलन' के दूसरे दिन लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने भाग लिया। इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में देश-विदेश के शहरों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञों और नगर निकायों से जुड़े अधिकारियों ने सहभागिता की। महापौर ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लेकर लखनऊ के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए।कार्यक्रम की शुरुआत जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन सत्र से हुई, जिसमें शहरों में बेहतर जल प्रबंधन, चौबीसों घंटे स्वच्छ जल आपूर्ति, उपयोग किए गए जल के पुनः उपयोग, नदियों के संरक्षण तथा कम लागत वाली नई तकनीकों के उपयोग पर चर्चा की गई। महापौर ने कहा कि तेजी से बढ़ते

शहरों में जल संरक्षण और सुनियोजित उपयोग अत्यंत आवश्यक है।इसके बाद स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन पुनर्प्राप्ति विषय पर विचार-विमर्श हुआ। शहरों में कचरा कम करने, गीले और सूखे कचरे को अलग करने, कचरे से ऊर्जा उत्पादन, निर्माण अपशिष्ट के पुनः उपयोग और आधुनिक शहरी सफाई व्यवस्था पर जोर दिया गया। प्रदर्शनी कक्ष में विभिन्न संस्थाओं द्वारा नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जहां महापौर ने प्रतिनिधियों से संवाद भी किया।दोपहर में आयोजित परिचर्चा सत्र में किफायती आवास, भूमि और वित्त के बेहतर उपयोग, सार्वजनिक-निजी सहभागिता मॉडल के माध्यम से आवास निर्माण तथा नवीन आवासीय नवाचारों पर चर्चा हुई। इसके बाद शहरी अवसंरचना वित्तपोषण पर आयोजित सत्र में नगर निकायों के लिए धन जुटाने के नए उपाय, नगरपालिका बांड, हरित वित्त और परियोजनाओं को सुरक्षित ढंग से आगे बढ़ाने की व्यवस्थाओं पर मंथन हुआ। सम्मेलन में डिजिटल प्रशासन भी प्रमुख विषय रहा। नागरिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्मार्ट उपयोगिता सेवाएं, साइबर सुरक्षा और आंकड़ा आधारित कर प्रणाली जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाएं सहज और पारदर्शी ढंग से मिल सकें।इसके अतिरिक्त हरित भवन तकनीक, ऊर्जा संरक्षण प्रणाली, पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। शहरी नेतृत्व, नागरिक सहभागिता और समावेशी नगर नियोजन पर भी विस्तृत चर्चा हुई।सम्मेलन में परिपत्र अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट से ऊर्जा, त्वरित निर्माण तकनीक और सार्वजनिक निर्माण कार्यों की मजबूती जैसे विषय भी प्रमुख रहे।इस अवसर पर महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों से नई तकनीक और बेहतर नगर प्रबंधन के अनुभव प्राप्त होते हैं। इन अनुभवों का उपयोग कर लखनऊ को स्वच्छ, आधुनिक और सतत शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

चौपटिया में इच्छापूर्ति श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न, भक्ति और उल्लास से गूंजा क्षेत्र

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के चौपटिया क्षेत्र स्थित फाटक जियालाल (गेट के अंदर पुराने पीपल के पास) में नवनिर्मित इच्छापूर्ति श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में गुरुवार को मूर्ति स्थापना एवं प्राण-प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य आयोजन श्रद्धा, भक्ति तथा उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया।कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करती हुई पुनः मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों और जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बनाते रहे। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई, जिससे पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया।

यूट्यूब से कमाई का बुलबुला फूट रहा

भारत में तीन दशक पहले डिजिटल क्रांति आई तो भारत कंप्यूटर और इंटरनेट का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। वैसे ही डेढ़ दशक पहले सोशल मीडिया की क्रांति हुई तो भारत उसका भी सबसे बड़ा बाजार बना। भारत में अभी फेसबुक, यूट्यूब, गूगल आदि के सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता हैं। इसी तरह दो साल पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की क्रांति हुई उसका भी सबसे बड़ा बाजार भारत बन गया है। भारत में ओपन एआई का इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। जिस तरह से भारत आईटी क्रांति और सोशल मीडिया क्रांति का बाजार बना है उसी तरह एआई क्रांति का भी बाजार बना है। लेकिन अब इस बाजार के डायनेमिक्स बदल रहे है।

अमेरिका की एआई कंपनियों ने मार्केटिंग की दिशा में अगला कदम बढ़ा दिया है। खबर है कि अब उनके एआई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मुफ्त नहीं होगा। पहले चरण में इसमें विज्ञापन इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एआई का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलने पर विज्ञापन चलेगा। अगर किसी को विज्ञापन मुक्त सेवा लेनी है तो उसे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मार्केटिंग का यह तरीका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा पहले से आजमाया जाने लगा है। प्रीमियम सर्विस के लिए पैसे देने होते हैं और मुफ्त सर्विस में विज्ञापन चलते हैं। इस विज्ञापन से अरबों डॉलर की कमाई होती है और वह पूरा पैसे अमेरिका जाता है। सोचें, विज्ञापन भारत के उत्पादों का होता है और उनके खरीदार भी भारत के लोग होते हैं। लेकिन उसका विज्ञापन करने वाला प्लेटफॉर्म विदेशी है। पहले विज्ञापन का प्लेटफॉर्म अखबार, पत्रिकाओं और टेलीविजन चैनलों का होता था। बाद में इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शामिल हुए। धीरे धीरे उन्होंने बाजार पर कब्जा करना शुरू किया। सरकारों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन के नए नियम बनाए। आज विज्ञापन का सबसे ज्यादा हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जाता है। उसमें गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है।

ऐसा नहीं है कि इसका लाभ सिर्फ अमेरिकी कंपनियों ने उठाया। उन्होंने भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को कमाई का माध्यम भी उपलब्ध कराया। भारत में रील बनाना और डिजिटल कंटेंट बना कर कमाई करना एक वैकल्पिक रोजगार बना। ऐसा रोजगार, जिसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं थी लेकिन पिछले ही साल बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने डाटा इतना सस्ता कर दिया कि लाखों लोग डिजिटल कंटेंट बना कर कमाई कर रहे हैं। उन्होंने रीलबाजी को एक रोजगार बताया। इतना ही नहीं इस साल जब मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया तो उसमें 15 हजार कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनाने का प्रावधान किया । सोचें, दुनिया के सभ्य और विकसित देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के लैब्स बना रहे हैं वही भारत में कंटेंट क्रिएशन के लैब बनने है!

परंतु इस रोजगार की राह भी अब मुश्किल हो गई है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दर्शकों और पाठकों तक रीच घटाई है। साथ ही मोनेटाइजेशन को कम किया है। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर तो पहले भी कम पैसे मिलते थे लेकिन यूट्यूब वीडियोज से लोगों को अच्छी खासी कमाई होती थी। पहले तो इनकी पैरेंट कंपनी मेटा ने वीडियो की लंबाई और गुणवत्ता के आधार पर भुगतान के नए नियम बनाए। इसमें छोटे यानी शॉर्ट वीडियोज और रील्स के लिए भुगतान काफी कम कर दिया। लंबे वीडियो पर अगर दर्शक ज्यादा देर टिकता था तो उसमें ज्यादा भुगतान के नियम बने। इस तरह 30 सेकेंड, तीन मिनट या उससे ज्यादा, 10 मिनट या उससे ज्यादा और 30 मिनट या उससे ज्यादा की अवधि वाले वीडियो की श्रेणियां बनाई गईं। पहले ये कंपनियां अनापशनाप पैसे देती थीं। लेकिन बाद में 10 मिनट का वीडियो अगर 10 हजार लोग देखते हैं तो एक डॉलर का भुगतान होने लगा। अब इसे और कम कर दिया गया है। एक बहुत ही चर्चित और वस्तुनिष्ठ खबरें दिखाने वाले सोशल मीडिया जर्नलिस्ट का कहना है कि उनके लंबे वीडियो पर पांच लाख व्यूज के बावजूद तीन हजार रुपए मिल रहे हैं। जाहिर है अब यह स्वरोजगार भी संकट में है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व अमेरिकी कंपनियों की कमाई में कमी हुई है। उनका विज्ञापन का राजस्व बढ़ रहा है लेकिन अब वे इस राजस्व को शेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं। तभी उन्होंने इन्फ्लूएंसर्स का पेआउट कम करना शुरू किया है। इस तरह यूट्यूब से कमाई का बुलबुला फूट रहा है। ऐप आधारित कैब सर्विसेज हों या ऐप आधारित फूड डिलीवरी की सेवा हो, इन सबमें पहले जिस तरह की कमाई होती थी वह भी बहुत कम हो गई है।

देशी कंपनियों के सामने हार्ले डेविडसन की चुनौती

अजीत द्विवेदी

भारत और अमेरिका के बीच दोपक्षीय व्यापार वार्ता चलती रहेगी लेकिन उससे पहले अंतरिम समझौते की घोषणा हो गई है। जिस दिन घोषणा हुई यानी समझौते का फ्रेमवर्क और साझा बयान जारी हुआ उसके अगले दिन, आठ फरवरी को पता नहीं अमेरिका के अखबारों में किसी भारतीय उत्पाद का विज्ञापन छपा या नहीं, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में सभी बड़े अखबारों में पहले पन्ने पर पूरे पेज पर अमेरिकी मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन का विज्ञापन छपा। 125 सीसी की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की कीमत तीन लाख रुपए से कम बताई गई। ध्यान रहे यह कोई सामान्य मोटरसाइकिल नहीं है। यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन श्रृंखला का प्रतीक उत्पाद है। पहली बार राष्ट्रपति रहते डोनाल्ड ट्रंप इसी बाइक पर लगने वाले सौ फीसदी से ज्यादा टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हुए थे। उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहा था। बाद में भारत सरकार ने इस पर लगने वाला शुल्क कम किया। अब खबर है कि नए समझौते के तहत इस पर जीरो टैरिफ लगेगा। भारत में मोटरसाइकिल का बाजार बहुत बड़ा है और अब देशी कंपनियों के सामने हार्ले डेविडसन की चुनौती है।

बहरहाल, अमेरिका के साथ होने वाले सौदे को लेकर बहुत सी बातें कही और लिखी जा चुकी हैं। जैसे पहले भारतीय उत्पादों पर तीन फीसदी टैरिफ लगता था अब 18 फीसदी लगेगा और भारत में अमेरिकी उत्पादों पर औसतन 15 फीसदी टैरिफ लगता था, जिसको शून्य किए जाने की खबर है। इसी तरह भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है और अमेरिका से खरीद बढ़ा दी है। ऐसे ही भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करेगा। यह तेल भारत को महंगा पड़ेगा। फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट सामने आने और रूस से तेल खरीद की वजह से भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को वापस लेने के राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश की प्रति सामने आने के बाद कुछ नई और दिलचस्प चीजें पता चली हैं। ट्रंप के कार्यकारी आदेश में लिखा हुआ है कि अगर भारत ने फिर रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो उसके ऊपर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जा सकता है। सोचें, किसी संप्रभु राष्ट्र के लिए क्या कोई दूसरा देश इस तरह के आदेश और धमकी जारी कर सकता है? ट्रंप ने भारत के लिए जारी किया लेकिन सब अपनी सुविधा के हिसाब से उनकी अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे ही फ्रेमवर्क में एक दिलचस्प बात यह है कि भारत अगले पांच साल में अमेरिका से पांच सौ अरब डॉलर के सामान खरीदेगा। यानी हर साल भारत को एक सौ अरब डॉलर के सामान खरीदने हैं। सवाल है कि भारत क्या खरीदेगा? अभी अमेरिका से भारत की औसत सालाना खरीद 40 अरब डॉलर की है। इसको दोगुने से ज्यादा बढ़ाना है। भारत अमेरिका से ऐसा क्या खरीदना शुरू करेगा कि उसका आयात दोगुने से ज्यादा बढ़ कर सौ अरब डॉलर यानी करीब नौ लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा? यह सही है कि भारत ने तेल खरीद बढ़ा दी है। तेल व गैस की खरीद थोड़ी और बढ़ाई जा सकती है। कुछ विमान व विमानों के कल पुर्जों की खरीद बढ़ जाएगी लेकिन क्या इससे भारत का आयात दोगुना हो जाएगा? कम से कम पहले साल में तो नहीं होने वाला है।

भारत दुनिया के दूसरे देशों से सस्ती और जरुरत की चीजें छोड़ कर अमेरिका से ज्यादा और गैरजरूरी चीजों की खरीद करे तब तो बात अलग है। अन्यथा ऐसे हर साल नौ लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदना मुश्किल होगा

भारत दुनिया के दूसरे देशों से सस्ती और जरुरत की चीजें छोड़ कर अमेरिका से ज्यादा और गैरजरूरी चीजों की खरीद करे तब तो बात अलग है। अन्यथा ऐसे हर साल नौ लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदना मुश्किल होगा। अगर भारत ने समझौते की इस शर्त को पूरा नहीं किया तो क्या होगा? सबको पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक दक्षिण कोरिया के साथ क्या किया? उन्होंने दक्षिण कोरिया से समझौता किया और एक दिन अचानक कहा कि वह समझौते की शर्तों को ठीक से लागू नहीं कर रहा है इसलिए उसके ऊपर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाता है। भारत के सामने भी यह खतरा रहेगा।

ध्यान रहे अभी तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में संतुलन भारत के पक्ष में था। अमेरिका से भारत अभी करीब चार लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है और उसे सात लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बेचता है। दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ अमेरिका का व्यापार संतुलन ऐसा ही था। तभी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब तक अमेरिका सभी देशों के साथ व्यापार में घाटा उठाता रहा है, अब वे इसे बदलेंगे। यानी अब अमेरिका मुनाफा कमाएगा। भारत के साथ व्यापार में भी ऐसा ही होगा। अब व्यापार संतुलन अमेरिका के पक्ष में होगा। अगर भारत चाहता है कि ऐसा न हो तो वह अमेरिका से नौ लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा और उसे इससे ज्यादा का सामाना बेचना होगा। सोचें, अभी भारत सात लाख करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का सामान बेचता है अब अचानक तीन या चार लाख करोड़ रुपए का कौन सा सामान बेचने लगेगा कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में झुके? यह भी ध्यान रखने की जरुरत है कि यूरोपीय संघ के साथ भी भारत ने मुक्त व्यापार संधि की है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ भी संधि हुई है। इन देशों को भी सामान बेचना है। इसे एक अवसर माना जा सकता है। लेकिन क्या अवसर का लाभ उठाने के लिए भारत तैयार है? सौदे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वाणिज्य मंत्री ने उन वस्तुओं की सूची गिनाई, जिनका निर्यात भारत करेगा। उसमें सेब और एवाकाडो भी है। सोचें, भारत में अपने इस्तेमाल का एवाकाडो तंजानिया, पेरू, चिली, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से आता है तो भारत कहां से एवाकाडो अमेरिका को निर्यात करेगा। इसी तरह भारत में सेब की अपनी जरुरत अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड और चीन के सेब से पूरी होती है। बहरहाल, भारत को एक तरफ अनाज, फल आदि का उत्पादन बढ़ाना होगा, उन्हें पेस्टिसाइड से मुक्त करना होगा और अमेरिकी व यूरोपीय स्टैंडर्ड का करना होगा। उसके साथ ही अपना बुनियादी ढांचा भी मजबूत करना होगा। सरकार कह रही है कि उसने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया है। लेकिन अभी समझौते का अंतिम मसौदा सामने आना बाकी है।

सरकार ने सोयाबीन तेल पर से टैरिफ हटा दिया है, जबकि अभी तक उस पर 45 फीसदी टैरिफ लगता था। इसी तरह ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन को अनुमति दी गई और उस पर लगने वाले 14 फीसदी टैरिफ को जीरो किया गया है। बादाम पर 42 रुपए प्रति किलो और बादाम गिरि पर सौ रुपए किलो टैरिफ लगता था और अखरोट एक सौ फीसदी व अखरोट गिरि पर 120 फीसदी टैरिफ लगता था। उसे भी जीरो कर दिया गया है। इससे किसानों पर होने वाले असर का आकलन होना बाकी है लेकिन भारत को मिलने वाले आयात शुल्क में इससे अच्छी खासी कमी आएगी। सो, अगर भारत का निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ता है और आयात बढ़ता जाता है और अनेक चीजों पर आयात शुल्क कम हो जाता है तो भारत को विदेशी मुद्रा की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल, सौदे में कुछ तो गड़बड़ी है, जिसकी वजह से कोई खुल कर नहीं बात कर रहा है। सौदे के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री बताएंगे और रूस से तेल खरीदने के मामले पर वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि विदेश मंत्री जानें या तेल कंपनियां जानें। भारत में शासन की इतनी केंद्रीकृत व्यवस्था में पहली बार ऐसा विकेंद्रीकरण देखने को मिल रहा है।

टिप्पणी

परमाणु विनाश का खतरा

परमाणु अस्त्रों की होड़ से बचने के लिए संधि की शुरुआत 1970 के दशक से हुई। तब से हमेशा किसी ना किसी संधि का अस्तित्व रहा। मगर अब ऐसा नहीं है। इससे परमाणु हथियारों और मिसाइलों की नई होड़ का रास्ता साफ हो गया है।

पांच दशक में ऐसी स्थिति पहली बार आई है, जब दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा टालने की किसी संधि का अस्तित्व नहीं है। चार फरवरी को अमेरिका और रूस के बीच मौजूद न्यू स्टार्ट (स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी) की अवधि समाप्त हो गई। रूस ने अमेरिका से नई संधि होने तक न्यू स्टार्ट की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस तरह अमेरिका और रूस अब असीमित संख्या में परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए स्वतंत्र हैं। 2010 में हुई न्यू स्टार्ट के तहत दोनों देशों ने अधिकतम 1550 परमाणु अस्त्रों की तैनाती की सीमा तय की थी।

साथ ही प्रावधान था कि दोनों देश एक दूसरे की तैनाती के ठिकानों या अन्य परमाणु ठिकानों का निरीक्षण कर सकेंगे। इसके तहत अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों और पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की संख्या भी तय थी। परमाणु अस्त्रों की होड़ से बचने के लिए संधि की शुरुआत 1970 के दशक से हुई। तब से हमेशा किसी ना किसी संधि का अस्तित्व रहा। मगर अब ऐसा नहीं है। इससे परमाणु हथियारों और मिसाइलों की नई होड़ का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की दलील है कि चीन उसके लिए खतरा बन कर उभर रहा है, जो उपरोक्त संधि में शामिल नहीं था। चीन का कहना है कि उसके पास मौजूद परमाणु हथियार अमेरिका और रूस से बहुत कम हैं, इसलिए उसे इस विवाद में नहीं घसीटा जाना चाहिए।

एक आकलन के मुताबिक अमेरिका के पास कुल 3,700, रूस के पास 4,309 और चीन के पास लगभग 600 परमाणु हथियार हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने गोल्डेन डोम परियोजना पर काम शुरू किया है। यह मिसाइल रक्षा कार्यक्रम है। रूस और चीन का कहना है कि इसका निर्माण होने के बाद सामरिक समीकरण बदल जाएंगे। उसे देखते हुए उन्हें अपने परमाणु अस्त्रागार और मजबूत करने होंगे। दलील यह भी है कि गोल्डेन डोम न्यू स्टार्ट की भावना का उल्लंघन है। इस तरह सभी महाशक्तियों ने तर्क ढूंढ लिए हैं, जिसके परिणास्वरूप दुनिया पर परमाणु विनाश का खतरा और सघन हो गया है।

ब्लॉग

मुफ्त रेवड़ी संस्कृति जीवंत लोकतंत्र के लिये घातक

ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र की विडंबना यह है कि चुनाव आते ही जनसेवा का स्वरूप बदलकर जनलुभावन राजनीति में परिवर्तित हो जाता है। राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनावी सफलता का शॉर्टकट बना लिया है। मतदाताओं को तात्कालिक आर्थिक लाभ देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लगातार मजबूत हो रही है। आगामी तीन-चार माह में विधानसभा चुनाव होने है, इसी संदर्भ में जब असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुईं, तब इस संस्कृति का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी पृष्ठभूमि में देश की शीर्ष अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, ने मुफ्त की योजनाओं के अनियंत्रित विस्तार पर गंभीर टिप्पणी की। यह टिप्पणी केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को लेकर एक चेतावनी है।

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरेक उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं। जब राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्य मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा या नकद वितरण की घोषणाएं करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि यह संसाधन कहां से आएंगे और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? राजकोषीय अनुशासन किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का आधार है। यदि राज्य अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खजाने को खाली करता है, तो दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। जो धन बुनियादी ढांचे के निर्माण, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार और रोजगार सृजन में लगना चाहिए, वह वोटों की फसल काटने में खर्च हो जाता है। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। लोकतंत्र में मतदाता की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी जाती है। यदि मतदाता को परोक्ष रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर प्रभावित किया जाता है, तो यह स्वतंत्र निर्णय की भावना को कमजोर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने तार्किक प्रश्न उठाया कि राज्य रोजगार सृजन और कौशल विकास पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते? वास्तव में रोजगार ही स्थायी सशक्तीकरण का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने श्रम और कौशल से आय अर्जित करता है, तब उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। इसके विपरीत, निरंतर मुफ्त सुविधाएं व्यक्ति को निर्भर बनाती हैं। धीरे-धीरे परिश्रम की संस्कृति कमजोर पड़ती है और समाज में अकर्मण्यता की मानसिकता पनपने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकता का नाम है। चुनाव पूर्व घोषित योजनाओं की निष्पक्षता भी प्रश्नों के घेरे में है। जब आचार संहिता लागू रहने के दौरान बड़े पैमाने पर आर्थिक वितरण होता है, तो विपक्षी दल इसे असमान प्रतिस्पर्धा मानते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष निगरानी की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग पर आती है। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी दल मतदाताओं को अप्रत्यक्ष रिश्वत देकर चुनावी लाभ न ले। आचार संहिता का उल्लंघन केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में यह प्रवृत्ति और गहरी जड़ें जमा सकती है। निस्संदेह, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राज्यों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की खास तौर से देखभाल करें। हालांकि, जब राजस्व घाटे वाले राज्य मुफ्त की योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। विडंबना यह है कि जिस धनराशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम बनाने और शिक्षा की सुविधा को समृद्ध करने के लिये किया जाना चाहिए, वो राशि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये खर्च कर दी जाती है। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें।

यह भी समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं का हर स्वरूप गलत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत देना, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पहुंचाना, सामाजिक न्याय के तहत वंचित वर्गों को अवसर देना-ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु चुनावी मौसम में अचानक घोषणाओं की बाढ़ आ जाना और दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों की अनदेखी करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत नहीं है। यह राजनीतिक दलों के वैचारिक दिवालियेपन को दर्शाता है, जहां दूरदृष्टि की जगह तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल संस्थाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सजगता से भी आती है। यदि मतदाता केवल तात्कालिक लाभ देखकर मतदान करता है, तो वह अनजाने में ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जो अंततः उसी के भविष्य को प्रभावित करती है। परिपक्व मतदाता वही है जो घोषणाओं के पीछे की मंशा और आर्थिक व्यवहार्यता को समझे। वह यह पूछे कि पांच साल बाद राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विकास की दिशा क्या होगी और रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे। लोकतंत्र में वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

आज भारत स्वयं को वैश्विक मंच पर एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। हम विश्वगुरु बनने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यदि हमारी राजनीति लोकलुभावनवाद के जाल में उलझी रहेगी, तो यह संकल्प खोखला सिद्ध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव तभी सार्थक है जब हमारी नीतियां दूरदर्शी, संतुलित और टिकाऊ हों। मुफ्त की संस्कृति से बाहर निकलकर उत्पादकता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। यह समय आत्ममंथन का है। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि जनता को सशक्त बनाना केवल धन बांटने से संभव नहीं है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार-ये चार स्तंभ किसी भी राष्ट्र की मजबूती तय करते हैं। यदि इन पर निवेश बढ़ेगा, तो नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य पर बोझ कम होगा। वहीं, नागरिकों को भी यह ठानना होगा कि वे तात्कालिक प्रलोभनों के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देंगे। लोकतंत्र की सुदृढ़ता तभी सुनिश्चित होगी जब शासन और जनता दोनों अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।

निस्संदेह, चुनावी निष्पक्षता के लिये यह आवश्यक हो गया है कि चुनाव से पहले घोषित की गई या लागू की गई लोकलुभावनी नीतियों व योजनाओं की गहन पड़ताल की जाए। विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पिछले साल अक्तूबर में आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 15,600 करोड़ रुपये दिए गए थे। जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कदम था। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपरोक्ष रूप से रिश्वत देने के प्रयासों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही इस दिशा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई भी करनी चाहिए। निर्विवाद रूप से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। यह कार्य करने की मानसिकता को बाधित करती है और समाज में सरकार-निर्भरता एवं अकर्मण्यता की संस्कृति को जन्म देती है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो आर्थिक असंतुलन और राजनीतिक अविश्वास दोनों बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि नीतियों की पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और चुनावी निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यही लोकतंत्र की वास्तविक रक्षा है, यही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर IT रेड दूसरे दिन भी जारी, क्रसर एसोसिएशन अध्यक्ष के घर भी छापे

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग (IT) की छापेमारी जारी है। रेड को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लखनऊ स्थित उमाशंकर सिंह के आवास से इनकम टैक्स की टीम बुधवार रात 10:30 बजे निकली, लेकिन विपुल खंड स्थित ऑफिस में अभी भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है।

बलिया स्थित उनके SKY होटल, प्लांट और आवास के अलावा एक अन्य ठिकाने पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। सोनभद्र और वाराणसी में भी इनकम टैक्स की टीमें मौजूद हैं। आयकर विभाग की टीम ने कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त किया है। विधायक उमाशंकर सिंह, उनके

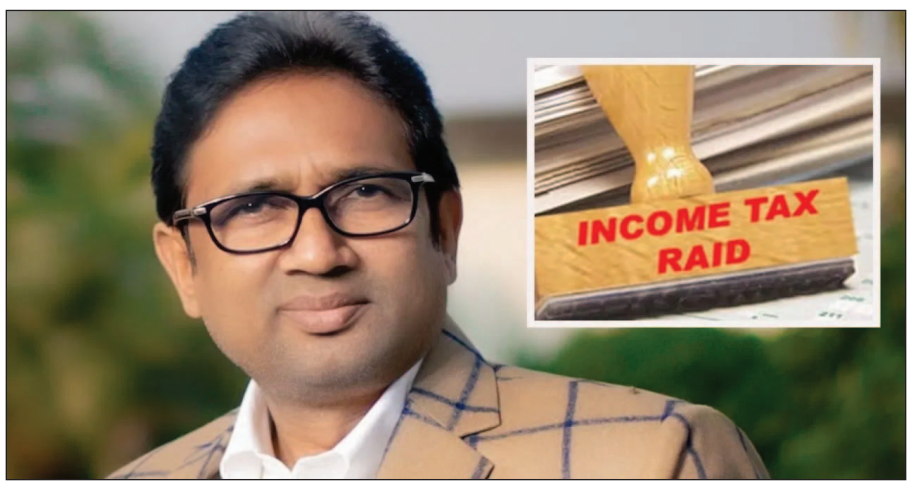

भाई, करीबी और बिज़नेस पार्टनर्स मिलाकर कुल तीस ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड बुधवार सुबह पड़ी थी। आयकर विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

आयकर विभाग की टीम क्रसर ऑनर्स एसोशिएसन के अध्यक्ष अजय सिंह , चंद्रभूषण गुप्ता,देवेंद्र केसरी समेत कई ठिकानों पर भी जांच कर रही है। विभाग के अधिकारी मेसर्स छात्र शक्ति के क्रसर प्लांट और ऑफिस की जांच कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो आयकर अधिकारियों को कई अहम दस्तावेज मिले हैं।

उमाशंकर सिंह पहली बार बसपा के टिकट पर 2012 में रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। उन्होंने 2017 और 2022 में भी बसपा के टिकट पर विजय दर्ज किया। इस बीच, बसपा विधायक के रिश्तेदार तथा बीजेपी नेता और प्रदेश की सरकार में मंत्री दिनेश सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस छापेमारी का विरोध किया है।

मंत्री ने और क्या लिखा?

मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, आयकर विभाग बलिया जिले के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर छापेमारी कर रहा है, जिनके परिवार में हमारी रिश्तेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य और देश के नेताओं के साथ-साथ आयकर विभाग एवं सभी अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि विधायक पिछले दो वर्षों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।

11 महीने पहले चर्चा में आए थे उमाशंकर

उमाशंकर सिंह 11 महीने पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में चर्चा में आए थे। उनके खिलाफ विजिलेंस ने जांच शुरू की थी। विजिलेंस ने उनके साथ ही उनकी पत्नी पुष्पा, बेटे युकेश और बेटी यामिनी के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों का ब्योरा जुटाना शुरू किया था। इसमें जमीन, मकान, फ्लैट, व्यावसायिक और कृषि संपत्तियां शामिल थीं। जांच के तहत विजिलेंस ने आईजी प्रयागराज को लेटर लिखकर संपत्तियों की डिलेट मांगी थी। इसके बाद आईजी ने संबंधित विभागों को जानकारी देने के निर्देश दिए थे। वाराणसी के उप-निबंधन कार्यालयों से भी रिकॉर्ड जुटाया गया था।

बरसाना की लठामार होली में टला बड़ा हादसा, बैरियर खुलते ही दौड़े श्रद्धालु, आधा दर्जन गिरकर चोटिल

आर्यावर्त संवाददाता

बरसाना (मथुरा)। लठामार होली के दौरान बुधवार शाम चार बजे उस समय अफरा-तफरा मच गई, जब पुलिस ने बैरियर को खोला और भीड़ के दबाव में कई श्रद्धालु जमीन पर गिर पड़े। इसे देख पुलिसकर्मी घबरा गए। हजारों की भीड़ में चंद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाकर स्थिति को संभाला और जमीन पर गिरे श्रद्धालुओं को उठाकर किनारे किया। इसमें आधा दर्जन युवक मामूली चोटिल हुए हैं। पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। बरसाना में रंगीली होली देखने के लिए करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालु बुधवार को बरसाना पहुंचे थे। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण के लिए कई बाक्स बनाए थे। इनमें श्रद्धालुओं को टुकड़ी में मंदिर के लिए एक से दूसरे बॉक्स की ओर छोड़ा जा रहा था। बुधवार शाम चार बजे संजय वकील तिराहा के पास पुलिस ने जैसे ही बैरियर खोला। भीड़ का रैला तेजी से आगे की ओर बढ़ा। हजारों की संख्या में चंद पुलिस कर्मी भीड़ के दबाव को संभाल नहीं सके। तेजी से आगे बढ़ रहे श्रद्धालुओं में से कुछ युवक भीड़ के दबाव में गिर पड़े। पीछे से भीड़ का दबाव बनता देख हालात बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई। जमीन पर गिरकर दबे युवकों की चीख-पुकार निकलने लगी। इसे देख बैरियर पर लगे पुलिस कर्मियों के हाथ-पैर फूल गए। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाई और युवकों को उठाने के लिए भीड़ के दबाव को रोकना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ में दबकर जमीन पर गिरे आधा दर्जन युवकों को सुरक्षित निकाला और किनारे करते हुए भीड़ को नियंत्रित किया। अधिकारियों को मामले की जानकारी हुई तो उनके भी होश उड़ गए।

बाल गृह में पोस्टर प्रतियोगिता के जरिए दिए डायरिया से बचाव के संदेश

आर्यावर्त संवाददाता

फ़िरोज़ाबाद। "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को स्थानीय राजकीय बाल गृह सुहागनगर में स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गयी। डायरिया के प्रति जागरूकता के लिए एक मैजिक शो का भी आयोजन जादूगर रवीद्र द्वारा किया गया। बाल गृह अधीक्षक रवि खान की अध्यक्षता में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में 40 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें कक्षा-10 के नीतीश पहले, कक्षा- नौ के तरुण दूसरे और कक्षा –छह के सोनू तीसरे स्थान पर रहे। कक्षा-आठ के गोपाल को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। रोल प्ले में पांच छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस मौके पर डायरिया रोकथाम और प्रबन्धन के बारे में विस्तार से बताया गया। जादूगर रवीद्र ने जादू के माध्यम से बताया कि डायरिया की चपेट में कई कारणों से बच्चे आ सकते हैं, जैसे- दूषित जल पीने से, दूषित हाथों से भोजन बनाने या बच्चे को खाना खिलाने, खुले में शौच करने या बच्चों के मल का ठीक से निस्तारण न करने आदि से। इसलिए शौच और बच्चों का मल साफ़ करने के बाद, भोजन बनाने और खिलाने से पहले हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह अवश्य धुलें। माताएं छह माह से ऊपर के बच्चों को स्तनपान कराती रहें और हमेशा साफ़-सुथरा पानी ही पिलायें। छह माह से कम उम्र के बच्चों को स्तनपान के अलावा बाहरी कोई भी चीज न दें यहाँ तक कि पानी भी नहीं। इस अवस्था में बाहरी चीज देने से संक्रमण का जोखिम बना रहता है। मां के दूध में बच्चे की जरूरत के मुताबिक़ पानी की मात्रा होती है, इसलिए बाहर से पानी न पिलाएं। पीएसआई इंडिया के प्रतिनिधि ने "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर अर्बन हैल्थ सेंटर हिम्मौरपुर के फार्मासिस्ट सौरभ यादव ने बच्चों का सामान्य चेकअप किया और ओआरएस, जिंक, कैल्शियम और आयरन का भी वितरण किया। इस अवसर पर पीएसआई इंडिया से राजेश कुमार, कैफुल हसन, बाल गृह के अध्यापक अंकित शर्मा, अमन कुमार , परामर्शदाता नीलम भारती, स्टाफ नर्स अदिति वर्मा, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) अध्यक्ष आशीष सिंह, हर गोविंद सिंह, ललिता सिंह तथा फिरदौस अंजुम उपस्थित रहीं।

'बदला पूरा हुआ...', नितिन की हत्या में पड़ोसी ने कातिलों की कैसे की मदद? ग्रेटर नोएडा हत्याकांड में खुला नया राज

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के लुक्सर गांव में नितिन नागर की दिनदहाड़े हुई निर्मम हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि साल 2024 में विनय नामक युवक की हत्या का बदला लेने के लिए इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई थी। नितिन को गोली मारने के बाद आरोपियों ने उसका गला भी रेत दिया था। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर 'बदला पूरा हुआ' इंस्टाग्राम स्टेटस लगाया।

पुलिस के अनुसार, मृतक नितिन नागर ने ही 2024 में विनय की हत्या की थी, जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था। उसी घटना का बदला लेने के लिए विनय के भाई और उसके मामा राजेश ने मिलकर नितिन की हत्या की साजिश रची। जांच में सामने आया है कि बदले की यह योजना करीब दो साल पहले ही बना ली गई थी, लेकिन आरोपी सही मौके

की तलाश में थे। नितिन के जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने हत्या की योजना को अमलीजामा पहनाया।

पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि नितिन और विनय दोनों गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में लाइटिंग का काम करते थे। इसी दौरान दोनों के बीच कई बार विवाद और झगड़े हुए थे। शुरुआत में यह मामूली कहासुनी थी, लेकिन धीरे-धीरे यह दुश्मनी में बदल गया। इसी रंजिश ने पहले विनय और फिर नितिन की हत्या जैसी घटनाओं को जन्म दिया।

पड़ोसी कर रहा था रेकी

जांच के अनुसार, हत्या से एक दिन पहले आरोपियों ने नितिन की गतिविधियों की रेकी की थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति नितिन पर नजर रख रहा था और उसकी हर गतिविधि की जानकारी बाकी आरोपियों तक पहुंचा रहा था। नितिन की पत्नी की तहरीर पर गांव के ही नितिन, जीते, सचिन, विपिन, मामा राजेश सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी सचिन और विपिन को बुधवार रात मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं।

वारदात के बाद इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया

नितिन की हत्या के बाद इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक स्टेटस ने जांच को नई दिशा दी। इसमें 'बदला पूरा हुआ' और 'बंदूक से जियो, बंदूक से मारो' जैसे शब्द लिखे थे तथा 2024 में मारे गए विनय की तस्वीर भी लगाई गई थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह स्टेटस किस आईडी से पोस्ट किया गया और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही। मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पहले से ही धमकियां दे रहे थे और हत्या के बाद खुलेआम बदले की बात स्वीकार कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार के

'मैंपढ़नाचाहतीथी, पापामुझेमाफकरदेना...', घरवालोंकोचाय पिलाई, फिर8वींकीछात्रानेकियासुसाइड, पापानेनामछोड़गईयेसंदेश

आर्यावर्त संवाददाता

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 15 वर्षीय छात्रा ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। छात्रा की जेब से मिला एक भावुक सुसाइड नोट उसकी मानसिक पीड़ा और पढ़ाई के प्रति उसके जुनून को बयां कर रहा है।

परिजनों के अनुसार, दोपहर करीब दो बजे आरती (परिवर्तित नाम) ने घर में सामान्य व्यवहार करते हुए सभी सदस्यों को प्यार से चाय बनाकर पिलाई। चाय पिलाने के बाद उसने कहा कि उसे नींद आ रही है और वह सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। एक घंटे बाद जब वह नहीं जागी, तो घरवाले उसे उठाने पहुंचे, जहां वह अचेत अवस्था में मिली।

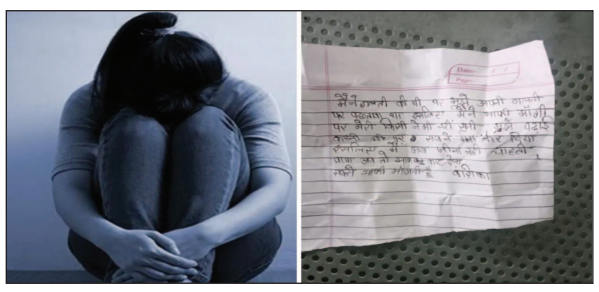

परिजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ। विजय प्रकाश ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने छात्रा द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने की आशंका जताई है।

"पापा मुझे माफ कर देना"

पुलिस को छात्रा की जेब से तीन पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी अधूरी ख्वाहिशों और दर्द का जिक्र किया है। छात्रा ने लिखा, 'मैंने गलती की थी, मुझे अपनी गलती का पछतावा था। मैंने माफी मांगी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। मुझे पढ़ाई करनी थी, पर सबने मना कर दिया। इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। पापा मुझे माफ कर देना।'

पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम

शहर कोतवाली पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, शुरुआत में परिजनों ने बीमारी से मौत की बात कही थी, लेकिन सुसाइड नोट मिलने के बाद मामला पूरी तरह बदल गया है। जांच अधिकारी ने कहा- शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। सुसाइड नोट के आधार पर परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस गलती और पढ़ाई को लेकर छात्रा दबाव में थी।

गांव में शोक की लहर

छात्रा की मौत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि वह पढ़ने में बहुत होशियार थी और हमेशा खुश रहती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली बेटी के मन में इतना बड़ा दुख छिपा है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय कनवाखेड़ा में पोस्टर व क्विज प्रतियोगिता आयोजित

आर्यावर्त संवाददाता

सीतापुर। जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय कनवाखेड़ा में बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग के तत्वावधान में "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के तहत पोस्टर और क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गयी। डायरिया के प्रति जागरूकता के लिए आयोजित प्रतियोगिता में 125 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें कक्षा-छह की दिव्यता शर्मा पहले, कक्षा-आठ की कहकशां दूसरे और कक्षा-छह की जोया तीसरे स्थान पर रहीं। कक्षा-पांच की जैनब को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से किया गया। पोस्टर और क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से रोटा वायरस, साफ सफाई, ओआरएस और जिंक की महत्ता को दर्शाने के

साथ ही छात्र-छात्राओं को डायरिया रोकथाम और प्रबन्धन के बारे में भी विस्तार से बताया गया। क्विज और पोस्टर के जरिए डायरिया से बचाव के जरूरी सन्देश दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्राधनाचार्य विष्णु कुमारी विमल ने कहा कि डायरिया की चपेट में कई कारणों से बच्चे आ सकते हैं, जैसे- दूषित जल पीने से, दूषित हाथों से भोजन बनाने या बच्चे को खाना खिलाने, खुले में शौच करने या बच्चों के मल का ठीक से निस्तारण न करने आदि से। इसलिए शौच और बच्चों का मल साफ़ करने के बाद, भोजन बनाने और खिलाने से पहले हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह अवश्य धुलें। डायरिया के दौरान ओआरएस से शरीर में पानी की कमी को रोकें।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नगरीय स्वास्थ्य केंद्र सदर डॉ शानू वर्मा ने कहा कि टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों को सारे टीके लगवाएं और रोटावायरस, विटामिन ए को लेना न भूलें। भोजन को ढककर रखें ताकि मक्खियाँ उस पर न बैठें। जिंक की खुराक को दस्त ठीक होने के बाद भी 14 दिनों तक जारी रखें। पीने के पानी को साफ़ रखें और पीने के पानी को निकालने के लिए डंडीदार लोटे का प्रयोग करें। छह माह से छोटे बच्चों को दस्त होने पर भी स्तनपान जारी रखना चाहिए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस) एवं पंचायती राज विभाग का भी सहयोग रहा। जिला बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमोद का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर पी एस आई इंडिया से कमलेश कुमार अश्वनी कुमार स्वास्थ्य विभाग से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजय श्रीवास्तव और शिवकांत जी का विशेष सहयोग रहा। स्कूल की अध्यापिका विष्णु कुमारी, पूनम यादव, फरजाना जैदी,शुभी गुप्ता का सहयोग रहा।

नोएडा के उत्तराखंड पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द, 400 छात्रों के भविष्य का क्या होगा?

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा के सेक्टर 56 स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्याता को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके माता-पिता को भी भविष्य की चिंता सताने लगी है। हालांकि, अधिकारियों ने समस्या का हल निकालने की बात कही है और बताया है कि बच्चों की शिक्षा पर असर नहीं होगा।

हालांकि, इस फैसले से अभिभावकों, छात्रों और शिक्षा विभाग में हलचल है। बोर्ड ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की मान्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह निर्णय शिक्षकों द्वारा लगाए गए वेतन कटौती, उत्पीड़न और महिला

शिक्षकों के साथ कथित शोषण के आरोपों की जांच के बाद लिया गया फैसला है।

400 छात्रों के भविष्य को लेकर अभिभावकों की चिंता

सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 400 छात्रों के भविष्य का क्या होगा? इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि बच्चों की जो परीक्षाएं चल रही हैं, उनको फिलहाल बाधित नहीं किया जाएगा। लेकिन अभिभावकों के मन में सबसे बड़ी चिंता यह है कि स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद बच्चों की पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ेगा।

डीआईओएस राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। जिन 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा चल रही है, उन्हें परीक्षा देने की पूरी अनुमति है और उनका सत्र प्रभावित नहीं होगा। वहीं 9वीं और 11वीं के छात्रों को 31 मार्च 2026 तक आसपास के अन्य सीबीएसई स्कूलों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

क्यों रद्द की गई मान्यता?

जानकारी के मुताबिक मामले की शुरुआत तब हुई जब पिछले वर्ष कई शिक्षकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उन्हें बैंक खाते में वेतन देने के बाद उसका एक हिस्सा नकद वापस करने के लिए दबाव बनाया जाता था। महिला शिक्षकों ने कार्यस्थल का माहौल असुरक्षित और तनावपूर्ण बताया।

कुछ शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जाता था। जब इसकी शिकायत जिला अधिकारी तक पहुंची तो सिटी मजिस्ट्रेट और जिला विद्यालय निरीक्षक की संयुक्त जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में कई आरोप सही पाए गए।

रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षकों के करीब 91 लाख रुपये बकाया थे, जिनमें से लगभग 68 लाख रुपये ही लौटाए गए, जबकि शेष राशि अभी भी लंबित बताई गई है। प्रशासन ने यह भी पाया कि वेतन का हिस्सा नकद लेने की शिकायतों में दम है।

इस पूरे मामले में शिकायतकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करे। इसके बाद सीबीएसई ने स्वतंत्र जांच कर 18 फरवरी को आदेश जारी करते हुए 9वीं से 12वीं तक की मान्यता रद्द कर दी।

अब क्या करेगा प्राधिकरण?

जिला प्रशासन एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की तैयारी में है, जो छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन्हें अन्य स्कूलों में प्रवेश दिलाने में मदद करेगा। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों का शैक्षणिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्था समय रहते पूरी कर ली जाएगी।

अधिकारी ने यह भी बताया कि कक्षा 8 तक की पढ़ाई पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इन कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय सीबीएसई और जिला प्रशासन की अगली समीक्षा बैठक के बाद लिया जाएगा। स्कूल को नई एडमिशन लेने पर फिलहाल पूरी तरह रोक लगा दी गई है और छोटी कक्षाओं के छात्रों को 9वीं और 11वीं में प्रमोट करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

1500 रुपये के लिए दोस्त बना हत्यारा, युवक की हत्या कर शव नाले में फेंका

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा के फेस 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 64 में 1500 रुपये के मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। फुटपाथ पर साथ सोने वाले दो दोस्तों के बीच पैसे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले सिर पर पत्थर से वार किया और फिर शव को पास के नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक राहुल और रविंद्र दोनों ही सेक्टर 64 इलाके में फुटपाथ पर रहते थे। दोनों दिहाड़ी मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे और रात में फुटपाथ पर ही सो जाते थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 1500 रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक पैसे को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच तनाव था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह विवाद इतना खतरनाक हो जाएगा। घटना वाले दिन दोनों के बीच फिर से पैसों को लेकर रात में झगड़ा हुआ और इस दौरान राहुल ने रविंद्र के सिर में पत्थर मारा, जिससे वह घायल हो गया और उसे नाले में धक्का दे दिया। नाले में पानी होने के कारण रात में ही उसकी मौत हो गई। घटना के अगले दिन सुबह जब लोगों ने देखा तो रविंद्र का शव पानी में तैर रहा था। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि साथ में रहने वाले राहुल ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

लड़कियों की वो 5 आदतें जो लड़कों को बिल्कुल नहीं होती बर्दाश्त

कहते हैं कि, जब लड़का और लड़की प्यार में होते हैं तो वो एक दूसरे की हर चीज को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की 5 ऐसी आदतें होती हैं जो लड़को को न चाहते हुए भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे।

रिश्तों की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही नाज़ुक भी होती है लड़के और लड़कियां सोचने, महसूस करने और हालात को समझने के तरीके में अक्सर अलग होते हैं। कई बार लड़के अपनी परेशानी खुलकर जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत खलती रहती हैं। वे बहस से बचने के लिए चुप रह जाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें सब कुछ मंज़ूर है। धीरे-धीरे यही छोटी-छोटी बातें रिश्ते में तनाव, दूरी और गलतफहमियों की वजह बन जाती हैंय

अक्सर देखा गया है कि प्यार में होने के बावजूद कुछ व्यवहार लड़कों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ये आदतें जानबूझकर नहीं होतीं, बल्कि कभी सेफ्टी, कभी ज्यादा उम्मीदों और कभी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से होते हैं। लेकिन जब ये बार-बार दोहराई जाती हैं, तो लड़कों को घुटन महसूस होने लगती है। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी आदते हैं तो लड़कों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती हैं।

हर बात पर शक करना

ज्यादातर लड़कियों में शक करने की आदत होती है। ये आदत उनमें देखने को मिलती है तो पार्टनर को लेकर पजेसिव होती है। ऐसे में बार-बार फोन चेक करना, दोस्तों के नाम पूछना या देर से जवाब मिलने पर सवालों की बौछार करना लड़कों को ये आदत घुटन भरी लगती है। एक वक्त ऐसा आता है जब लड़कों को ये आदत बर्दाश्त नही होती है।

छोटी-छोटी बातों पर बार-बार ताने देना

कई लड़कियों में ताने देने की बहुत ज्यादा आदत होती है। उन्हें तो लगता है कि वो बस अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। लेकिन सामने वाले को ये काफी इरिटेट करता है। खासतौर पर टोका-टाकी या पुरानी गलतियां याद दिलाना लड़कों को चिढ़ा देता है। इससे आपस में दूरी भी बढ़ सकती है।

हर वक्त फोन में उलझे रहना

आजकल डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया चलाना मानो लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा हो गया है। लोग इसे अब मनोरंजन के तौर पर नहीं बल्कि कई वजहों से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और फोन में उलझे हुए हैं तो ये सामने वाले को इरिटेट कर सकता है। खासतौर पर जब किसी लड़के के साथ लड़की बैठी हो और फोन में सारा ध्यान लगाए हुए हो। ये आदत लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है।

जरूरत से ज्यादा ड्रामा करना

हर इंसान एक सा नहीं होता है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, जिन्हें चीजों को बढ़ाने की आदत होती है। हर मुद्दे को बड़ा बनाना, रोना-धोना या बात-बात पर इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली आदक लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है।

दूसरों से बार-बार तुलना करना

हर इंसान का नेचर और पर्सनैलिटी अलग होती है। ऐसे में किसी की भी किसी दूसरे से तुलना करना बिल्कुल गलत है। लेकिन कई बार लड़कियां अपने पति या फिर बॉयफ्रेंड की तुलना किसी दूसरे लड़के से करती हैं। ये बाद लड़कों को बहुत ठेस पहुंचाती है। इससे एक समय पर रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है।

नंबर मांगना

रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताते हैं, सबसे पहली गलती है किसी लड़की से मिलते ही उसका नंबर मांग लेना। ऐसा करने से आप डेसपेरेट दिख सकते हैं और जल्दबाजी दिखना बात को वहीं खत्म कर सकता है।

पास्ट के बारे में जानकारी

ज्यादातर लड़कियों को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी शेयर करने में समय लगता है। ऐसे में बार-बार उनके पुराने रिश्तों या निजी बातें जानने की कोशिश करना उन्हें चुभ सकता है।

हर वक्त उपलब्ध रहना

शुरुआत में ही बहुत अधिक बातें करना, 'कहां हो', 'क्या कर रही हो?' इस तरह के सवाल बार-बार करना या हर वक्त चैट पर उपलब्ध रहना भी लड़कियों को असहज महसूस करा सकता है। इससे उन्हें लग सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई और काम नहीं है। किसी भी रिश्ते में स्पेस देना बहुत जरूरी है।

जरूरत से ज्यादा तारीफ

इन सब से अलग जवाल भट्ट कहते हैं, बार-बार 'तुम बहुत हॉट हो' जैसी ओवर सेंसुअल तारीफें भी लड़कियों को पसंद नहीं आतीं। तारीफ करें, लेकिन सच्ची और सम्मानजनक भाषा में। ऐसे में जरूरत से ज्यादा क्लिंगी या चाइल्डिश व्यवहार से बचें और अपने पार्टनर को उसकी आजादी दें।

सिर्फ 'मथुरा-वृंदावन' ही नहीं इन जगहों की होली भी होती है कमाल, रंगों में हो जाएंगे सराबोर

होली का नाम आते ही ज़हन में सबसे पहले मथुरा-वृंदावन की लठमार और फूलों वाली होली की तस्वीर ही आती है। राधा-कृष्ण की नगरी में रंगों का जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम दिखता है, वह वाकई अनोखा होता है। जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग भी आते हैं। कुछ लोग तो हर साल मथुरा की इन होली का जश्न मनाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मथुरा और वृंदावन में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में होली का एक अलग ही जश्न देखने को मिलता है। इन जगहों पर अलग-अलग तरह से होली सेलिब्रेट की जाती है, जो वाकई देखने लायक होती है।

होली सिर्फ रंग लगाने का त्योहार नहीं, बल्कि यह दिलों से दूरियां मिटाने, बीते गिले-शिकवे भूल जाने और रिश्तों में नई मिठास घोलने का एक मौका होता है। अलग-अलग राज्यों और शहरों में य उत्सव अलग रंग-रूप में देखने को मिलता है। कहीं सूखे गुलाल की खुशबू में, कहीं ढोल-नगाड़ों की गूंज, तो कहीं पारंपरिक व्यंजनों और लोककथाओं का स्वाद। चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसी ही 5 जगहें जहां की होली एक बार तो आपको जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए।

बरसाना की लट्ठ मार होली

बरसाना की होली दुनियाभर में लठमार होली के नाम से मशहूर है। यहां महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष ढाल लेकर खुद को बचाते हैं। यह परंपरा राधा-कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी मानी जाती है। रंग और भक्ति का यह अनोखा संगम बरसाना की होली को बिल्कुल अलग बनाता है। 25 फरवरी को बरसाना की लट्ठ मार होली मनाई जाएगी, जो वाकई एक बार तो आपको जरूर देखनी चाहिए।

वाराणसी में भी होली का जश्न

काशी की होली में आध्यात्म और मस्ती का अनूठा मेल देखने को मिलता है। यहां की सिर्फ दिवाली ही नहीं बल्कि होली भी काफी कमाल की होती है। यहां गंगा घाटों पर रंगों के साथ-साथ संगीत, भांग और ठंडाई की धूम रहती है। शिवभक्तों की टोली, ढोल-नगाड़ों की गूंज और घाटों पर उड़ता गुलाल सब मिलकर वाराणसी की होली को बेहद खास बनाते हैं।

शांतिनिकेतन की होली

पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में होली को बसंत उत्सव के रूप में मनाई जाती है। यहां रंगों के साथ रवींद्रनाथ टैगोर की परंपरा जुड़ी है। छात्र-छात्राएं पीले वस्त्र पहनकर गीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए वसंत और होली का स्वागत करते हैं। ये होली शोर से ज्यादा सौंदर्य और कला की पहचान मानी जाती है। अगर आपको भी शांत और सुकून देने वाली होली मनानी है तो आप शांतिनिकेतन जा सकते हैं।

उदयपुर की शाही होली भी कमाल

उदयपुर की होली शाही अंदाज के लिए जानी जाती है। यहां मेवाड़ राजघराने की परंपराओं के साथ होलिका दहन और भव्य जुलूस निकाले जाते हैं। राजसी पोशाकें, सजे-धजे हाथी-घोड़े और लोकनृत्य उदयपुर की होली को एक शाही उत्सव बना देते हैं। शाही फील के लिए आपको एक बार उदयपुर की होली जरूर मनानी चाहिए।

प्रयागराज की धूम-धड़ाके वाली होली

संगम नगरी प्रयागराज में भी होली का एक अलग ही जश्न देखने को मिलता है। यहां कपड़ा फाड़ होली काफी मशहूर है। जहां मोहल्लों में सामूहिक होली खेली जाती है। जिसमें पुरुष एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ते हैं। इतना ही नहीं म्यूजिक और मेल-मिलाप कर होली को एक बेहद प्यारा रंग दिया जाता है।

दांत पीले क्यों हो जाते हैं? सिर्फ गलत खाना है या कोई साइंटिफिक कारण

दांतों में अगर पीलापन आ जाए तो काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। कई लोग दांतों का पूरा ध्यान भी रखते हैं। लेकिन फिर भी दांत पीले हो जाते हैं। आज हम इस आर्टिकल में बताएंगे कि दांत पीले होने की पीछे कि कौन-कौन सी वजह हैं।

सफेद दांत कॉन्फिडेंस के साथ ही एक प्यारी मुस्कान भी देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों रोज ब्रश करते हैं, मीठा कम खाते हैं, फिर भी उनके दांत धीरे-धीरे पीले दिखने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हम साफ-सफाई का ध्यान रख रहे हैं, तो फिर दांत पीले क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब दांतों की बनावट, उम्र, लार की प्रकृति, दवाइयों के असर और यहां तक कि जेनेटिक कारणों तक में छिपा हो सकता है। दांत केवल बाहर से दिखने वाली सफेद परत नहीं होते, बल्कि उनके अंदर भी कई परतें होती हैं, जिनका रंग समय के साथ बदल सकता है।

अगर आपके दांत भी धीरे-धीरे पीले हो गए हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हम जानेंगे कि, लगातार दांतों की सफाई और सही खानपान के बाद के बाद दांत आखिर पीले क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं और इन्हें कैसे वापस सफेद किया जा सकता है।

गलत खान-पान का दांतों पर असर

दांतों का पीला होना सिर्फ गलत खान पान नहीं बल्कि अनहेल्दी खान पान की वजह से भी हो सकता है। अक्सर चाय, कॉफी, कोला, रेड वाइन जैसे गहरे रंग के ड्रिंक पीने से पिगमेंट दांतों की ऊपरी परत (एनामेल) पर चिपक जाते हैं और समय के साथ दांतों को पीला बना देते हैं। इसके अलावा,अगर आप भी अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो भी इसका असर हमारे दांतो पर पड़ता है।
दरअसल, ज्यादा एसिडिक या प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन दांतों के एनामेल को नुकसान पहुंचाता है। जिससे नीचे की पीली परत (डेंटिन) ज्यादा दिखाई देती है और दांतों का रंग पीला नजर आने लगता है।

दांतों के पीला होने के साइंटिफिक कारण

पबमेड के मुताबिक, दांतों का पीला होना सिर्फ गलत खान-पान की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके दो तरह के कारण होते हैं।

बाहरी और अंदरूनीः बाहरी कारणः जब हम बार-बार चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, रेड वाइन पीते हैं या तंबाकू-सिगरेट का सेवन करते हैं, तो इनके रंग और रसायन दांतों की ऊपर वाली परत पर चिपक जाते हैं। धीरे-धीरे ये परत साफ न हो पाने पर दांत पीले या भूरे दिखने लगते हैं। ये वही दाग हैं जो बाहर से लगते हैं और सही सफाई या डेंटल ट्रीटमेंट से काफी हद तक हट सकते हैं।

अंदरूनी कारणः कुछ कारण दांतों के अंदर से जुड़े होते हैं। जैसे, दांत के अंदर मौजूद डेंटिन का रंग, बचपन में कुछ दवाइयों (जैसे टेट्रासाइक्लिन) का असर, शरीर की कुछ बीमारियां या उम्र बढ़ने के साथ दांतों की ऊपर वाली सफेद परत (एनामेल) का पतला हो जाना। जब एनामेल पतली होती है, तो नीचे की पीली परत ज्यादा दिखने लगती है, जिससे दांत पीले नजर आते हैं।

जेब पर भारी पड़ेगा कौन? क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, किसका ब्याज है कम

पर्सनल लोन पर आमतौर पर क्रेडिट कार्ड ईएमआई से कम ब्याज लगता है। पर्सनल लोन में अब ज्यादा समय और आसान रीपेमेंट ऑप्शन मिलते हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आपकी जेब के लिए पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड कर्ज कौन सबसे ज्यादा मुफीद है।

जब आप किसी बड़े खर्चे के बारे में सोच रहे हों — जैसे मेडिकल बिल, गैजेट, अचानक परिवार में आने वाला खर्च — तो आमतौर पर दो ऑप्शन सबसे पहले सामने आते हैं। बैंक से पर्सनल लोन लें, या अमाउंट को क्रेडिट कार्ड ईएमआई में बदलें। दोनों ऊपर से एक जैसे दिखते हैं: फिक्स्ड टाइम पीरियड, फिक्स्ड मंथली खर्च, बस हो गया। लेकिन उनमें से एक लगभग हमेशा जितना दिखता है उससे ज्यादा महंगा होता है। अंतर इंटरेस्ट रेट, हिडन चार्ज और अगर कुछ गलत हो जाता है तो हर ऑप्शन कितना माफ करने वाला है, इसमें है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपकी जेब पर सबसे ज्यादा भारी है कौन, क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन?

क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का इंट्रस्ट रेट?

आजकल पर्सनल लोन के इंट्रस्ट रेट आमतौर पर एक बड़ी रेंज में होते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सैलरी वाला और स्टेबल है, तो आपको रेट कम से कम 1000 से शुरू होते दिख सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल कमज़ोर है, तो रेट तेजी से बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड ईएमआई शायद ही कभी सस्ते होते हैं। जब कोई बैंक नो-कॉस्ट ईएमआई का विज्ञापन करता है, तब भी इंट्रस्ट रेट अक्सर प्रोसेसिंग फीस या कम डिस्काउंट के जरिए शामिल होता है। स्टैंडर्ड कार्ड ईएमआई इंट्रस्ट, जब सालाना होता है, तो आसानी से 1824 परसेंट को पार कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो, उतने ही अमाउंट और टाइम के लिए, पर्सनल लोन पर आमतौर पर कार्ड ईएमआई से कम इंट्रस्ट रेट लगता है — जब तक कि आप बहुत कम कार्ड ऑफर के लिए क्वालिफ़ाई न करें।

नो-कॉस्ट ईएमआई का भ्रम

नो-कॉस्ट ईएमआई सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कई मामलों में, दुकानदार इंट्रस्ट अमाउंट के बराबर डिस्काउंट देता है, इसलिए ईएमआई सस्ती लगती है। आप पैसे नहीं बचा रहे हैं — आप पहले से डिस्काउंट पाने के बजाय पूरी कीमत चुका रहे हैं। क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर आमतौर पर प्रोसेसिंग फीस और GST भी लगता है। यह फीस आपके प्रिंसिपल को कम नहीं करती, लेकिन आपकी कॉस्ट बढ़ा देती है। पर्सनल लोन में भी प्रोसेसिंग फीस होती है, लेकिन आमतौर पर उन्हें साफ-साफ बताया जाता है और जब आप ऑफर कम्पेयर करते हैं तो उन्हें ध्यान में रखा जाता है।

आपकी मंथली फ्लेक्सिबिलिटी पर असर

पर्सनल लोन ईएमआई फिक्स्ड, प्रेडिक्टेबल और आपके रोज के खर्च से अलग होती है। एक बार इसे सेट अप करने के बाद, आपका क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी के लिए फ्री रहता है। क्रेडिट कार्ड ईएमआई आपकी कार्ड लिमिट को कम कर देती है। इससे ईएमआई पूरी तरह से पे होने तक आपका अवेलेबल क्रेडिट कम हो जाता है। अगर आपके कार्ड की लिमिट कम है, तो यह आपको चुपके से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकता है — जिससे आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान हो सकता है। अगर आप कार्ड की ईएमआई मिस करते हैं, तो नतीजे और भी बुरे होते हैं। लेट फीस ज्यादा होती है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और आपके पूरे कार्ड बैलेंस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो सकता है। पर्सनल लोन इसकी तुलना में ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और थोड़े ज्यादा माफ करने वाले होते हैं।

टेन्योर और कंट्रोल

पर्सनल लोन ज्यादा टेन्योर देते हैं, अक्सर पांच साल तक। इससे बड़े खर्चों के लिए ईएमआई को मैनेज करने में मदद मिलती है। क्रेडिट कार्ड ईएमआई आमतौर पर छोटी होती हैं, आमतौर पर 6 से 24 महीने। कम टेन्योर का मतलब है ज़्यादा मंथली खर्च, भले ही हेडलाइन रेट एक जैसा दिखे। प्रीपेमेंट एक और फर्क है। कई पर्सनल लोन कुछ महीनों के बाद पार्ट-प्रीपेमेंट की इजाज़त देते हैं, कभी-कभी कम से कम पेनल्टी के साथ। क्रेडिट कार्ड ईएमआई को बिना किसी कहे जाने वाले नो-कॉस्ट फायदे को खोए जल्दी बंद करना मुश्किल होता है।

तो कौन सा आपके ज्यादा पैसे बचाता है?

अगर खर्च ज्यादा है और किसी स्पेशल मर्चेंट ऑफर से जुड़ा नहीं है, तो पर्सनल लोन लंबे समय में लगभग हमेशा सस्ता पड़ता है। क्रेडिट कार्ड ईएमआई कम समय की खरीदारी के लिए सही हो सकती है, जहां आपको कुल खर्च का पक्का पता हो, समय कम हो, और ऑफर सच में ट्रांसपेरेंट हो। फिर भी, यह देखना सही है कि आप कौन सा डिस्काउंट छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी गलती सिर्फ सुविधा के आधार पर चुनना है। क्रेडिट कार्ड ईएमआई आसान लगती हैं, लेकिन अक्सर वे ज्यादा खर्चीली होती हैं। पर्सनल लोन में थोड़ा ज्यादा पेपरवर्क होता है, लेकिन वे आमतौर पर आपके वॉलेट का ज्यादा ध्यान रखते हैं।

ओयो की पैरेंट कंपनी प्रिज्म के बोर्ड में शामिल हुए पूर्व सेबी प्रमुख अजय त्यागी

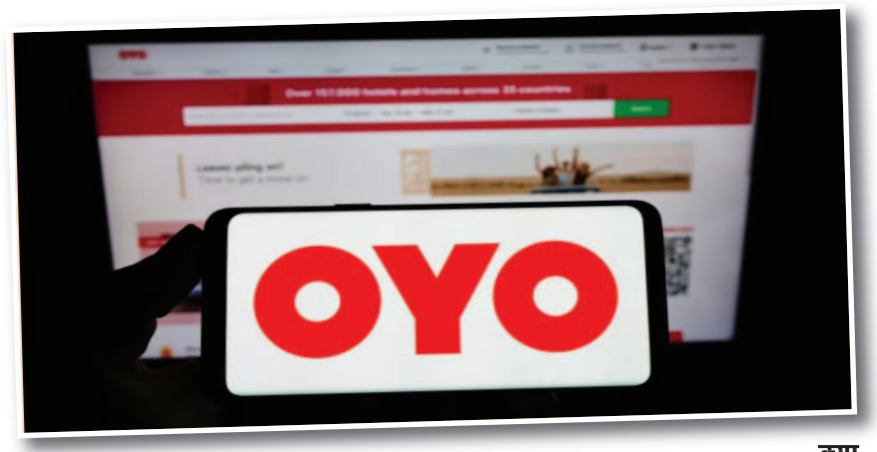

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी ओयो की पैरेंट इकाई प्रिज्म ने अपने आगामी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम से पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। कंपनी ने बुधवार को घोषणा की कि उसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व चेयरमैन अजय त्यागी को अपने निदेशक मंडल (बोर्ड) में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी में शासन और जवाबदेही पर जोर

ओयो की पैरेंट कंपनी में नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब यह सार्वजनिक बाजारों तक अपनी पहुंच बनाने और विकास के लिए अपने शासन ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। प्रिज्म के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अजय त्यागी पूंजी बाजार विनियमन, गवर्नेंस और सार्वजनिक संस्थानों के प्रबंधन में अपनी गहरी समझ लेकर आए हैं। अग्रवाल के अनुसार, त्यागी का यह अनुभव कंपनी के गवर्नेंस मानकों और दीर्घकालिक जवाबदेही को मजबूत करते हुए प्रिज्म के विस्तार में अमूल्य साबित होगा।

6,650 करोड़ रुपये का आईपीओ प्रस्तावित

प्रिज्म का यह रणनीतिक कदम इसके मेगा आईपीओ की तैयारियों से सीधे तौर पर जुड़ा है। हाल ही में 31 दिसंबर को सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रिज्म ने बाजार नियामक सेबी के पास गुप्त तरीके का उपयोग करते हुए आईपीओ के जरिए 6,650 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए हैं। इस प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम के तहत कंपनी का मूल्यांकन 7 से 8 अरब डॉलर के बीच आंके जाने की मजबूत संभावना है।

क्या है अजय त्यागी की खासियत?

1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे अजय त्यागी के पास वित्तीय क्षेत्र की नीतियों, बाजार विनियमन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का व्यापक अनुभव है। उन्होंने 2017 से 2022 तक सेबी के चेयरमैन के रूप में भारत के प्रतिभूति बाजारों की निगरानी की, साथ ही नियामक व प्रकटीकरण ढांचे को मजबूत करने और प्राथमिक व द्वितीयक बाजार की गतिविधियों को प्रबंधित करने में अहम भूमिका निभाई। सेबी से पहले, वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव थे। वहां उन्होंने पूंजी बाजार, निवेश नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और दिवालियापन कानून जैसे व्यापक वित्तीय सुधारों का काम संभाला। वर्तमान में वे कई भारतीय कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा के मोर्चे पर, त्यागी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक और कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है, साथ ही उनके पास हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी है।

दिग्गजों से भरा बोर्ड

अजय त्यागी अब शासन, उपभोक्ता व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक निवेश की विशेषज्ञता वाले एक बेहद अनुभवी बोर्ड का हिस्सा बन गए हैं। प्रिज्म के मौजूदा बोर्ड में उटाह स्टेट यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंसी प्रोफेसर विलियम स्टीव अल्ब्रेक्ट, स्टारबक्स कॉरपोरेशन के पूर्व सीएफओ ट्रॉय मैथ्यू अलस्टेड, और पद्म श्री से सम्मानित दीपा मलिक जैसे स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। इसके अलावा, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स के बेजुल सोमाया, सॉफ्टबैंक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सुमेर जुनेजा और अकासा एयर के सह-संस्थापक आदित्य घोष भी बोर्ड के अहम सदस्य हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण को कमला हैरिस ने झूठा बताया, अमेरिकियों को गुमराह करने का लगाया आरोप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे झूठ से भरा हुआ बताया। इसके साथ ही उन पर अर्थव्यवस्था, मतदान के अधिकार और ईरान के मुद्दों पर अमेरिकियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ट्रंप के भाषण के एक दिन बाद, हैरिस ने बुधवार (स्थानीय समय) को अपने सबस्टैक शो द पारनास पर्सपेक्टिव के होस्ट आरोन पारनास को बताया कि उन्होंने भाषण देखा और पाया कि यह आम परिवारों के सामने आने वाली वास्तविकताओं से अलग था।

इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में दक्षिणी राज्यों की अपनी यात्राओं का वर्णन किया। उन्होंने मिसिसिपी में एक ऐसी मां से मिलने का किस्सा सुनाया, जिसका चार लोगों के लिए साप्ताहिक किराने का बजट मात्र 150 डॉलर था। हैरिस ने कहा, 'कार्ट में जो कुछ भी था, वह उसके बच्चों के लिए ही था' और आगे बताया कि उस मां ने उनसे कहा कि जो कुछ भी उनके बच्चे नहीं खाएंगे, वह खुद खा लेगी। ₹वह बोतलबंद पानी लेने के लिए चलकर गई क्योंकि वह नल का पानी नहीं पी सकती, क्योंकि पानी भूरा और जहरीला है। यही है अमेरिका।'

हैरिस ने प्रस्तावित खर्च प्राथमिकताओं की भी आलोचना की। उन्होंने पूछा, 'जब आप मेडिकेड में 1 ट्रिलियन डॉलर की कटौती करते हैं, तो इससे किसके लिए आवाज उठती है? वहीं दूसरी ओर, अमेरिका के सबसे अमीर लोगों के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स कटौती की जा रही है। यही हमारे देश में अभी हो रहा है।₹ मतदान के अधिकारों के मुद्दे पर, हैरिस ने सेव एक्ट का कड़ा विरोध किया, जिसे ट्रंप ने कांग्रेस से पारित करने का आग्रह किया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस उपाय के तहत लोगों को मतदान के लिए पंजीकरण कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं, उन्होंने दावा किया कि लगभग 40 प्रतिशत अमेरिकियों के पास ये दस्तावेज नहीं हैं।

अमेरिकी लोग एक और युद्ध के लिए तैयार नहीं

विदेश नीति पर बात करते हुए, हैरिस ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पहले दावा किया था कि उन्होंने उनके कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसे पूरी तरह से बकवास बताया। उन्होंने कहा कि अब वह इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों को भेज रहे हैं, जिससे यह बहुत संभव है कि अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं को युद्ध में तैनात किया जाएगा।₹ हैरिस ने आगे कहा, "अमेरिकी जनता एक और युद्ध नहीं चाहती और न ही वे अपने बेटों और बेटियों को ऐसी कार्रवाई शुरू करने के लिए भेजना चाहते हैं जिसे टाला जा सकता है और जो कि संभव भी है।"

क्या है स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन

स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को दिया जाने वाला वार्षिक भाषण है, जिसमें विधायी प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। देश की स्थिति का आकलन किया जाता है। यह अक्सर चुनावों से पहले घरेलू और विदेश नीति संबंधी बहसों की दिशा तय करता है। 2026 के मध्यावधि चुनाव कांग्रेस पर किसका नियंत्रण होगा, यह तय करेंगे। इन्हें व्यापक रूप से मौजूदा राष्ट्रपति के एजेंडे पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जाता है और ये अमेरिकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीति की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

'इस्राइल में फलस्तीनियों के मुद्दे उठाएं PM मोदी', ईरानी विदेश मंत्री ने भारत से संबंधों पर दिया ये बयान

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गाजा में इस्राइल की सैन्य कार्रवाई की निंदा की है और पीएम मोदी से अपील की है कि वे इस्राइल दौरे पर फलस्तीनियों के अधिकारों का मुद्दा उठाएं। पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर इस्राइल में मौजूद हैं। अराघची ने आरोप लगाया कि गाजा में इस्राइल की कार्रवाई नरसंहार के बराबर है और तेहरान, इस्राइल के साथ जुड़ना ठीक नहीं समझता। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस्राइल में पीएम मोदी फलस्तीनियों और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के मुद्दे पर भी बात करेंगे। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अराघची ने कहा, 'दुर्भाग्यवश, इस्राइल ने पूरे गाजा को तबाह किया है। 75 हजार लोग मारे गए हैं और यह सिर्फ दावा नहीं है बल्कि तथ्य है, जिसकी पुष्टि गाजा मुद्दे पर काम करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने की है। यह एक नरसंहार है।

'जबरन कब्जे वाले इलाके खाली करो', पीओके पर भारत की पाकिस्तान को फटकार, सुनाई खरी-खरी

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए तगड़ी फटकार लगाई है। भारत ने इस्लामाबाद पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर का विकास पथ पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं के बिल्कुल विपरीत है। 23 फरवरी से 31 मार्च तक आयोजित हो रहे सत्र में 25 फरवरी को आयोजित उच्च स्तरीय सत्र के दौरान भारत के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस समूह ने खुद को एक सदस्य देश के लिए 'प्रतिबिंब कक्ष' के रूप में इस्तेमाल होने दिया है।

अनुपमा सिंह ने कहा कि हम इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान का लगातार दुष्प्रचार ईर्ष्या से भरा हुआ है। सिंह ने भारत के उस चिरस्थायी रुख को दोहराया कि जम्मू और कश्मीर 'भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा।' उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, 1947 में इस क्षेत्र का भारत में विलय पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय था। उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र से संबंधित एकमात्र लंबित विवाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है और उन्होंने इस्लामाबाद से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को खाली करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नियमित सत्र के उच्च स्तरीय खंड में, जिनेवा में प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा, 'पाकिस्तान और ओआईसी द्वारा उच्च स्तरीय खंड के दौरान उठाए गए मुद्दों के जवाब में भारत को अपने उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ा है। हम इन आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार को दोहराकर, ओआईसी यह प्रकट करता है कि वह किस हद तक एक सदस्य देश के प्रभाव में आ गया है, और उस देश की राजनीतिक बाध्यताओं के लिए एक प्रतिध्वनि कक्ष बनकर रह गया है। पाकिस्तान का निरंतर दुष्प्रचार ईर्ष्या से भरा है। हम इसे महत्व नहीं देना चाहते, लेकिन तथ्यों के आधार पर इसका खंडन करने के लिए हम कुछ बिंदु उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत बयानबाजी या दुस्साहसी दुष्प्रचार इस अटल तथ्य को नहीं बदल सकता कि जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय था।

कनाडा के बदले सुर, खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या मामले में भारत के दखल को नकारा

ओटावा। भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक ताकत का ही असर है कि कनाडा, भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कवायद में जुटा है। यही वजह है कि कनाडा ने ये मान लिया है कि कनाडा की धरती पर होने वाले अपराधों में भारत की कोई संलिप्तता नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं और कनाडा सरकार के इस कदम को दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के तौर पर देखा जा रहा है। जो जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के अंतिम दिनों में बेहद खराब दौर में पहुंच गए थे।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, कनाडा सरकार के अधिकारियों ने बताया 'अगर भारत, कनाडा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दे रहा होता तो शायद प्रधानमंत्री कार्नी, भारत दौरे पर जाते ही नहीं।' अधिकारियों ने कहा, हमारी भारत सरकार के साथ इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही विदेशी हस्तक्षेप से बचने के लिए हमारे पास मजबूत सुरक्षा उपाय हैं।

कनाडा सरकार के अधिकारियों ने ये साफ नहीं किया कि कनाडा सरकार ने भारत को लेकर अपना रुख बदलने का फैसला कब किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इसे लेकर पीएम मोदी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ व्यवस्थित रूप से बातचीत की गई। अधिकारियों ने कहा कि इन मुद्दों को नियमित रूप से उठाया गया और उन्हें विश्वास है कि आगे भी इस पर सार्थक चर्चा जारी रहेगी।

कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। कनाडा की तत्कालीन ट्रूडो सरकार ने भारत पर निज्जर की हत्या कराने का आरोप लगाया और इसे संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया था। हालांकि भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और निज्जर की हत्या में संलिप्तता से इनकार किया। इस मामले को लेकर दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़े की दोनों ने अपने कुछ राजनयिकों को वापस बुला लिया।

हालांकि ट्रूडो सरकार के सत्ता से बाहर होने और मार्क कार्नी के सत्ता संभालने के बाद से भारत कनाडा के रिश्तों में फिर से बेहतरी हो रही है। मार्क कार्नी भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे का मकसद दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूत करना है। इसे कनाडा द्वारा व्यवहारिक विदेश नीति अपनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है।

भारत आज दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है और बड़ा बाजार है। ऐसे समय में जब अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में तनाव है तो कनाडा चीन और भारत जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में जुटा है और भारत को लेकर उसके रुख में बदलाव को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का आरोप- अजीत पवार प्लैन क्रैश मामले को दबा रही है फडणवीस सरकार

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने गुरुवार को अजीत पवार विमान दुर्घटना मामले में महाराष्ट्र सरकार की निष्क्रियता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अधिकारियों पर डीजीसीए और वीएसआर वेंचर्स को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने सवाल उठाया कि मुंबई पुलिस ने एनसीपी विधायक रोहित पवार की मांग पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार क्यों किया। उन्होंने संकेत दिया कि प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्तक्षेप से अधिकारियों के व्यवहार पर असर पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि डीसीपी को विधान भवन से फोन आया था, जिसके बाद कमिश्नर का रवैया बदल गया। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि कई राजनेताओं ने वीएसआर वेंचर्स में निवेश किया है। इसके साथ ही मौजूदा मंत्रियों के भी कंपनी से वित्तीय संबंध हैं, जिससे उचित कार्रवाई न होने का कारण स्पष्ट हो सकता है।

सरकार मामले को दबा रही

संजय राउत ने कहा 'इस मामले को दबाया जा रहा है। आप कुछ छुपा रहे हैं। कई नेताओं ने इस वीएसआर कंपनी में पैसा लगाया है। जानकारी सामने आ रही है कि मौजूदा मंत्रियों के भी इस कंपनी से वित्तीय संबंध हैं। डीसीपी को एक फोन आया था। यह विधानसभा भवन से आया था। आप सामान्य मामलों में एफआईआर दर्ज करते हैं, तो यहां क्यों नहीं की गई? एक प्रभावशाली व्यक्ति का फोन आया, जिसके बाद कमिश्नर का व्यवहार बदल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशक विभाग (डीजीसीए) एक भ्रष्ट विभाग है, और कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाया है। उन्हें कई नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है।'

अब गुरुग्राम के शहरी झुग्गी-झोपड़ियों और मोहल्लों तक पहुंचेगी 'सेहत की गाड़ी'

गुरुग्राम (हरियाणा), एजेंसी। अनुभवी डॉक्टरों, आधुनिक उपकरणों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ से लैस, ₹सेहत की गाड़ी₹ (चौथी मोबाइल मेडिकल यूनिट) अब गुरुग्राम के झुग्गी-झोपड़ियों और मोहल्लों तक पहुंचकर लोगों की सेहत की जांच-परख के साथ आवश्यक परामर्श की सुविधा भी प्रदान करेगी। यह पहल स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा की गयी है। इसकी शुरुआत बृहस्पतिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) व सिविल सर्जन डॉ. लोकवीर सिंह ने सीएमओ कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनुज गर्ग भी मौजूद थे। ज्ञात हो कि सोहना, पटौदी और फारुखनगर ब्लॉक में पहले ही यह पहल शुरू की जा चुकी है।

इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन ने कहा कि यह पहल इस मकसद से शुरू की गई है कि कोई भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह मोबाइल मेडिकल यूनिट एक तय रूट चार्ट के हिसाब से गुरुग्राम ब्लॉक के चुने हुए मोहल्लों में पहुंचेगी, मोहल्ले वालों की आम बीमारियों की जांच करेगी और सलाह देगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो वे रेफर करने में भी मदद करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायरॉइड, डेंगू, मलेरिया और दूसरी आम बीमारियों की जांच के साथ-साथ मां और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा समुदाय स्तर पर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा आईडी) बनाने में भी मदद की जाएगी। इस मौके पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनुज गर्ग ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट जिले के दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की कमी को दूर करने में मदद करेंगी। यह प्रोग्राम मोहल्ले वालों के लिए फायदेमंद होगा और ये यूनिट रेगुलर हेल्थ कैंप लगाने और पीरियड्स में साफ-सफाई के प्रबन्धन के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करेंगी। इस मौके पर नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर और चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर तरुण कत्याल ने अपनी टीम के सदस्यों ईवीपी और हेड- क्लेम मैनेजमेंट-डॉ. शांति बंसल, वाइस प्रेसिडेंट-प्रियंका शर्मा, प्रोजेक्ट लीड निशा गाठिया के साथ उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत, मोबाइल मेडिकल यूनिट के ज़रिए ओपीडी सेवाएं, और परामर्श की सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही रिप्रोडक्टिव, महिला और बाल स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच), किशोरों की काउंसलिंग, हाइजीन, न्यूट्रिशन और गैर संचारी रोगों से जुड़ी जनजागरूकता गतिविधियाँ भी आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर पीएसआई इंडिया के डायरेक्टर-प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हितेश साहनी और अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे।

द केरल स्टोरी 2 पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, लगे 16 कट, लिप लॉक सीन किए कम

द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से ही विवादों से घिरा हुआ। फिल्म के खिलाफ रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। इसी बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को /र 16+ सर्टिफिकेशन के साथ पास कर दिया है। हालांकि मेकर्स को फिल्म में 16 कट्स लगाने या बदलाव करने को कहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, सीबीएफसी ने द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड के मेकर्स को फिल्म में लगभग 16 कट या बदलाव करने के लिए कहा है। किसिंग विजुअल्स और रेप सीन को 50 प्रतिशत कम कर दिया गया।

एक लिप-लॉक सीन को 7 सेकंड कम करने के लिए कहा गया। रेप सीन को 20 सेकंड छोटा कर दिया गया। एक सीन, जिसमें एक महिला को थप्पड़ मारा जा रहा है, और दूसरा सीन जिसमें एक महिला के सिर पर मारा जा रहा है, दोनों को 2 सेकंड कम कर दिया गया।

एक सीन में जहां आरोपी का घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है, सीबीएफसी ने उसे बदलने के लिए कहा गया। इसके अलावा उन्होंने तीन डायलॉग बदलने और एक शब्द म्यूट करने के लिए कहा गया।

तमाम कट और बदलावों के अलावा, फिल्म बनाने वालों से एक डिस्क्लेमर जोड़ने के लिए कहा गया है, जिसमें यह लिखा हो कि द केरल स्टोरी 2 सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उनसे यह भी कहा गया कि डिस्क्लेमर टेक्स्ट को स्क्रीन पर 2 मिनट और 3 सेकंड ज्यादा देर तक रहने दें, और उसके साथ एक वॉइस-ओवर भी शामिल करें।

सीबीएफसी ने मेकर्स को डायलॉग के साथ पूरी सक्रिप्ट सबमिट करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि इन दावों को साबित करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दें कि कहानी सच्ची घटनाओं से ली गई है। बोर्ड को एक माइनर की कास्टिंग के बारे में एक कंसेंट लेटर भी दिया गया।

तमाम बदलाव के बाद, 16 फरवरी को फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया गया। फिल्म का रनटाइम 131 मिनट और 24 सेकंड है, यानी यह 2 घंटे, 11 मिनट और 24 सेकंड लंबी है। कामाख्या नारायण सिंह की निर्देशित द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड 27 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी।

ईशा मालवीय की डेब्यू फिल्म इश्कां दे लेखे का ट्रेलर रिलीज, प्यार-पागलपन और जुनून की दिखी झलक, 6 मार्च को रिलीज होगी मूवी

भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, डांसर, लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस 17 फेम ईशा मालवीय की पहली फिल्म इश्कां दे लेखे का ऑफिशियल ट्रेलर सोमवार को रिलीज कर दिया गया। अभिनेत्री रोमांटिक पंजाबी फिल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। इश्कां दे लेखे का ट्रेलर स्पीड रिकॉर्ड्स, पैनोरमा स्टूडियोज और डायमंडस्टार वर्ल्डवाइड यूट्यूब चैनलों ने आपस में कोलैबोरेशन के तहत अपलोड किया है, जिनके चैनलों पर कुल मिलाकर लगभग 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं।

चैनल ने मूवी का ट्रेलर रिलीज करते हुए डिसक्रिप्शन में लिखा, एक बार फिर प्यार में पड़ने के लिए तैयार हो जाइए! स्पीड रिकॉर्ड्स प्रस्तुत करता है 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित पंजाबी प्रेम कहानी इश्कां दे लेखे का ट्रेलर। शानदार गुरनाम भुल्लर और खूबसूरत ईशा मालवीय अभिनीत यह पंजाबी फिल्म उन सभी लोगों के लिए बनाई गई है, जिन्होंने कभी दिल से प्यार किया है।

प्रतिभाशाली मनवीर बरार द्वारा निर्देशित, इश्कां दे लेखे बड़े पर्दे पर पंजाबी रोमांस को एक नई परिभाषा देने के लिए तैयार है। लेख और सुखीं भिंडी जैसी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद गुरनाम भुल्लर एक और उत्कृष्ट कृति के साथ वापसी कर रहे हैं और यह फिल्म किसी जादू से कम नहीं है। यह नई पंजाबी फिल्म प्यार की कहानी है और पंजाबी सिनेमा की सदाबहार क्लासिक बनने के लिए तैयार है।

ट्रेलर की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी की बेल से होती है, जिसके बाद गुरनाम भुल्लर का सीन दिखाया जाता है और एक दमदार पंजाबी रोमांटिक डायलॉग सुनने को मिलता है, जिसमें कहा जाता है, जदो प्यार हद से गुजर जाए, उने मोहब्बत कहते हैं। जदो मोहब्बत हद से गुजर जाए, उनो पागलपन कहते हैं। पर जदो पागलपन हद से गुजर जाए, तो...

इसके बाद ट्रेलर में एक रोमांटिक पंजाबी गाना सुनने को मिलता है और सीन में ईशा मालवीय परीक्षा हॉल में बैठी नजर आ रही है। मूवी में अभिनेत्री (जसनीत) का किरदार निभा रही हैं। इसके बाद आगे ट्रेलर में एक और डायलॉग सुनने को मिलता है, जिसमें कहा जाता है, कई बार कुड़यिा दा पहला प्यार, बहुतों ने प्यार कर चुके होते हैं।

ट्रेलर में एक के बाद एक कई बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिलते हैं और यह एक डायलॉग के साथ समाप्त भी होता है, जहां कहा जाता है, जे रब सानु प्यार करने वाले ने पागल बना सकता है, तो क्या प्यार करने वाले रब नू थोड़ा सा पागल नहीं बना सकते हैं क्या? ट्रेलर में ईशा मालवीय और गुरनाम भुल्लर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है।

2 मिनट 25 सेकेंड के ट्रेलर में लव, हेट, प्यार, पागलपन, जुनून और बर्बादी के साथ कई लाजवाब सीन देखने को मिलते हैं। फैंस मूवी के ट्रेलर को काफी पसंद कर रहे हैं और कुछ ही घंटे में चैनल पर हजारों व्यूज आ चुके हैं। वहीं, कमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। इश्कां दे लेखे मूवी सिनेमाघरों में 6 मार्च को रिलीज होने वाली है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

फिल्म में ईशा मालवीय और गुरनाम भुल्लर के अलावा राणा रणबीर, मिंटू कप्पा, बलविंदर बुलेट, गुरलीन चोपड़ा, गुरप्रीत रंधावा, जसबीर गिल, मोहनी तूर, बाबर खान, कवि सिंह, शनाया खन्ना, मनिंदर वेली, अर्शदीप कौर भट्टी, डेवी सिंह, सीरत प्रीत, रंग हरजिंदर, पुष्पक चौंटा, हेजल सप्रा और अर्शदीप सिंह गिल जैसे कलाकार भी पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरेंगे। इस फिल्म की कहानी जस्सी लोहका ने लिखी है और गुरनाम भुल्लर मूवी के निर्देशक हैं। वहीं, कार्यकारी निर्माता जसविंदर लाहरी हैं।

आंखों पर काला चश्मा और गले में रुद्राक्ष की माला, 'भूत बंगला' से सामने आया अक्षय कुमार का नया लुक

अक्षय कुमार की आगामी फिल्म 'भूत बंगला' अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म के जरिए अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की हिट जोड़ी 16 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। यही कारण है कि फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आज मेकर्स ने फिल्म का एक नया मोशन पोस्टर जारी किया है।

मेकर्स की ओर से जारी किए गए फिल्म के नए मोशन पोस्टर में अक्षय कुमार एक डरावने सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे हैं। इस सिंहासन पर डरावने भूतों के सिर बने हुए हैं, जो मुंह फैलाते नजर आ रहे हैं। इस पर बैठे अक्षय कुमार भी मुंह फैलाए हुए हैं।

आंखों पर काला चश्मा लगाए अक्षय अपने गले और हाथों में कई रुद्राक्ष और अन्य मालाएं पहने हुए हैं। जबकि एक हाथ में वो माला जप भी रहे हैं। एक लुंगी या धोती जैसी पहने अक्षय कुमार शर्टलेस नजर आ रहे हैं। अक्षय का ये लुक किसी तांत्रिक से मिलता-जुलता मालूम पड़ता है।

इस पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने एक मजेदार कैप्शन भी दिया है। कैप्शन में लिखा गया, 'दस को देंगे दस्तक, इंतजार करो तब तक। मस्ती शुरू होने दो।' इसके साथ ही मेकर्स ने एक बार फिर से फिल्म की रिलीज डेट भी याद दिलाई है, जो 10 अप्रैल है।

प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, तब्बू और परेश रावल भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में राजपाल यादव और मिथिला पालकर भी अहम किरदार निभाएंगे। मिथिला पालकर फिल्म में अक्षय की बहन के किरदार में नजर आएंगी। हालांकि, अभी तक फिल्म की कहानी और किरदारों के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com